मीडिया की घेराबंदी

UP में मीडिया के दमन पर CAAJ की रिपोर्ट

[प्रशासन की ज्यादती और फ़र्ज़ी मुकदमों से तंग आकर पहली बार उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह करना पड़ा। यह तस्वीर जून 2020 की फतेहपुर से है।]

मीडिया की

घेराबंदी

उत्तर प्रदेश में मीडिया के दमन की दास्तान (2017 से अब तक)

UP PUCL द्वारा समर्थित

Committee Against Assault on Journalists (CAAJ)

की रिपोर्ट

यह रिपोर्ट कोरोना-काल में स्वास्थ्य तंत्र के कुप्रबंधन, संसाधनों के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का शिकार हुए 600 से ज्यादा भारतीय पत्रकारों को समर्पित है।

विषय-वस्तु

1. रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

2. पाँच साल के आंकड़ों पर एक नज़र

3. पत्रकारों की हत्या के मामले

4. हिंसक हमलों के उपलब्ध विवरण

5. व्याख्यात्मक रिपोर्ट

6. रिपोर्ट के निहितार्थ और निष्कर्ष

7. अनुलग्नक

- लखीमपुर खीरी रमन कश्यप हत्याकांड पर PUCL की रिपोर्ट
- उत्तर प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बयान और पत्र

रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति (CAAJ) ने अपनी आख़िरी रिपोर्ट मार्च 2020 में जारी की थी जिसका शीर्षक था 'रिपब्लिक इन पेरिल'। उक्त रिपोर्ट में दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच दिल्ली में पत्रकारों पर हुए हमलों का विवरण था। इन हमलों के विश्लेषण में हमलों की प्रकृति के आधार पर समीक्षाधीन अवधि को तीन चरणों में बांटा गया था। इन चरणों के हमलों के लक्षण के बतौर जो तथ्य गिनवाये गये थे उनमें प्रमुख इस प्रकार थे:

1) मीडिया का ध्रुवीकृत चरित्र
2) हमलों का ध्रुवीकृत चरित्र
3) हमलों की आउटसोर्सिंग

उक्त रिपोर्ट का सार यह था कि बीते कुछ वर्षों में समाज में समाचारों को ग्रहण करने और धारणा बनाने को लेकर जैसा तीखा ध्रुवीकरण देखा गया है, उसी के आधार पर अब पत्रकारों पर हिंसा भी की जा रही है। इस प्रेक्षण का तात्कालिक संदर्भ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उपजा आंदोलन था जिसमें पत्रकारों के आइडीकार्ड यानी उनके संस्थान को देखकर इलाकों में हमले किये जा रहे थे। उक्त अवधि में अकेले दिल्ली में जो 32 घटनाएं सामने आयी थीं, उनमें हमला करने वाले ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनका सीधे तौर पर सत्ता प्रतिष्ठान से कोई लेना-देना नहीं था। ये अराजकीय तत्व थे, लेकिन इनके हमले सरकारी नैरेटिव के तर्ज पर थे। इसी को हिंसा की 'आउटसोर्सिंग' कहा गया था।

यह स्थिति दिल्ली के दंगों तक आते-आते राजकीय हमले में तब्दील होती दिखी, जहां न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कश्मीर जैसे राज्यों में पत्रकारों को पुलिस की ज्यादती का शिकार बनना पड़ा। यह स्थिति कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन से ठीक पहले तक थी। दो साल बाद आज की तारीख में पीछे मुड़ कर देखने पर ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के मसले पर राज्य पत्रकारों के खिलाफ तभी कमर कस चुका था। इस लिहाज से पत्रकारों के खिलाफ घटी पिछली घटनाएं एक ट्रेलर से ज्यादा कुछ नहीं थीं।

बीते दो वर्षों में प्रेस की आज़ादी के मोर्चे पर देश की तस्वीर कैसी बनी है, इसे विस्तार से समझने के लिए केवल एक टिप्पणी कारगर हो सकती है- मोबाइल संदेशों की जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर पेगासस के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था 'ऑरवेलियन कन्सर्न'। संदर्भ जॉर्ज ऑरवेल के कालजयी उपन्यास 1984 में दर्शाये गये राज्य ओशियनिया की सत्ता का था जो पूरी तरह निरंकुश है और अपने नागरिकों की जासूसी करवाती है।

उपन्यासकार ऑरवेल को उद्धृत करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा ने कहा, "यदि आपको कुछ गोपनीय रखना है तो उसे खुद से भी छुपाना पड़ेगा।" सर्वोच्च अदालत का कहना था कि कथित जासूसी के प्रकरण में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जो याचिकाएं लगायी गयी हैं वे

'ऑरवेलियन' चिंताओं को जन्म देती हैं, कि आप जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं और जो कुछ जानते हैं उस सब को सुनने, देखने और जानने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का दोहन किया जा सकता है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के निरंकुश और सर्वसत्तावादी होने की आशंका पर टिप्पणी की थी। महज तीन महीने बाद सर्वोच्च अदालत की आशंकाएं सही साबित हो गयीं जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक लंबी खोजी रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की कि भारत सरकार ने इज़रायल से पेगासस की खरीद की थी। "दि बैटल फॉर दि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबरवेपन' (दुनिया के सबसे ताकतवर साइबर हथियार के लिए होड़) शीर्षक से 31 जनवरी 2022 को प्रकाशित इस रिपोर्ट में लिखा गया है:

"जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के नारे पर सत्ता प्राप्त की थी, इज़रायल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। दशकों तक भारत ने एक नीति कायम रखी हुई थी जिसे वह "फलस्तीनी सरोकारों के प्रति वचनबद्धता" का नाम देता था लिहाजा इज़रायल के साथ उसका रिश्ता ठंडा बना रहा। मोदी का दौरा हालांकि काफी गर्माहट भरा रहा जहां उन्हें व प्रधानमंत्री नेतन्याहू को समुद्र तट पर नंगे पांव घूमते हुए सुनियोजित और सतर्क तरीके से दर्शाया गया। इस गर्मजोशी की इनके पास एक वजह थी। दोनों देश करीब दो अरब डॉलर के एक खरीद सौदे पर राजी हुए थे जिसमें अत्याधुनिक हथियार और गुप्तचरी का सामान शामिल था- जिस सौदे का आकर्षण था पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली। महीनों बाद नेतन्याहू ने भारत का एक दुर्लभ दौरा किया। जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इज़रायल के हक में वोट किया कि फलस्तीन के मानवाधिकार संगठनों को प्रेक्षक का दरजा न दिया जाय। भारत ने ऐसा पहली बार किया था।"

पेगासस जासूसी की कहानी जुलाई 2021 में उजागर हुई। भारत में कम से कम 174 ऐसे लोगों के नाम सामने आए जिनकी सरकारी जासूसी की गयी थी। इसमें पत्रकार तो थे ही, खुद भारत सरकार के मंत्री तक शामिल थे। फोन नंबरों के आधार पर जासूसी के शिकार व्यक्तियों से मीडिया संस्थानों ने जब दरयाफ्त की, तब जाकर यह बात सामने आयी कि कोई दो साल पहले ज्यादातर व्यक्तियों को वॉट्सएप की तरफ से जासूसी से आगाह करते हुए संदेश भेजे गए थे। इसके बाद यह उद्घाटन भी हुआ कि भीमा कोरेगांव प्रकरण में जिन पत्रकारों, समाजकर्मियों और वकीलों को जेल भेजा गया है उन सबकी इस माध्यम से न केवल जासूसी की गयी थी बल्कि उनके मोबाइल और लैपटॉप में ऐसे फर्जी दस्तावेज प्लांट किये गये थे जिनके आधार पर उन्हें अपराधी ठहराया जा सके। हिंदी पट्टी के कम से कम चार पत्रकार इस जासूसी का शिकार हुए- 'दस्तक नये समय की' पत्रिका की संपादक सीमा आज़ाद, वर्कर्स राइट्स के संपादक संदीप राय, चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय और झारखण्ड के स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह।

पेगासस प्रकरण का उद्घाटन यदि नहीं होता तो शायद यह समझने में दिक्कत आती कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने से लेकर जासूसी करने और उस पर हमला करने वाले तमाम संदिग्ध तत्वों के पीछे दरअसल सीधे तौर पर राज्य की भूमिका है। मार्च 2020 तक जैसे हमले पत्रकारों पर हुए, हम यही मानते रहे कि राजकीय ताकतों के साथ उन बाहरी तत्वों की भी स्वतंत्र भूमिका आवाज़ों को दबाने में है। पेगासस ने एक झटके में इस धुंध को छांट दिया है। इस धुंध के छंटने के बाद 2020 और

2021 में पत्रकारों पर हमले के आंकड़े जब हम सामने रख के देखते हैं, तो उनका आशय और उनमें छुपे हुए निहितार्थ बहुत साफ़ समझ में आते हैं। यहीं उत्तर प्रदेश अचानक महत्वपूर्ण हो उठता है।

उत्तर प्रदेश वैसे तो बाकी राज्यों की तरह एक अदद राज्य ही है लेकिन इसकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि यहां से केंद्र की सत्ता की राह निकलती है। जाहिर है, फिर भारत सरकार के नवीनतम प्रयोगों की प्रयोगशाला भी इसी राज्य को होना चाहिए। यह संयोग नहीं है कि कोरोना के नाम पर लगाये गये पहले लॉकडाउन से लेकर अब तीसरी लहर के छीजने तक सबसे ज्यादा जिस राज्य में अधिकारों और आवाज़ों पर कानूनी डंडा चलाया गया है, वह उत्तर प्रदेश है। प्रेस की आज़ादी पर बीते दो वर्षों में जितनी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें आयी हैं उन सब में उत्तर प्रदेश और कश्मीर को पत्रकारों पर हमले के मामले में अव्वल रखा गया है। कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे), राइट्स एंड रिस्क अनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) सहित प्रेस एम्बलम कैम्पेन व ठाकुर फाउंडेशन अनुदानित अध्ययन और ऐसे ही कुछ और सर्वेक्षणों में उत्तर प्रदेश को भारत में पत्रकारिता के लिए सबसे खतरनाक सूबा बताया गया है। सभी के आंकड़े इसकी बराबर पुष्टि करते हैं।

चूंकि उत्तर प्रदेश आज एक निर्णायक चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लिहाजा यहां बीते पांच वर्षों में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हुए हमलों को एक बार पीछे मुड़ कर देखना ज़रूरी है। जाहिर है, अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा इतना बड़ा है कि यदि हम संविधान के अनुच्छेद 19(अ) के अंतर्गत आने वाली सभी किस्म की नागरिक अभिव्यक्तियों और उनके उल्लंघन को शामिल करें तो फिर हमें पहले लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही उत्तर प्रदेश में दर्ज 6079 एफआइआर और इसमें आरोपित बनाये गये बीस हजार के आसपास व्यक्तियों का विश्लेषण करना पड़ेगा। समस्या की विराटता को समझने के लिए बस इतना जान लें कि 2020 में लगाये गये लॉकडाउन के पहले महीने में उत्तर प्रदेश में 19448 एफआइआर दर्ज किये गये और 60,258 व्यक्तियों पर आइपीसी की धारा 188 व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया (बार एंड बेंच, 17 अप्रैल 2020)। हालत यह हो गयी थी कि इतनी भारी संख्या में दर्ज की गयी एफआइआर को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगानी पड़ गयी।

यदि हम अपनी समीक्षा को केवल प्रेस की आजादी पर हुए हमलों के आंकड़े व विश्लेषण तक सीमित रखें तब भी एक और समस्या आड़े आती है। 2020 और 2021 के लॉकडाउन में यानी मोटे तौर पर दो साल के भीतर जितने पत्रकारों को महामारी अधिनियम के तहत नोटिस पकड़ाये गये हैं या जिनका उत्पीड़न हुआ है उसकी गिनती भी व्यावहारिक तौर पर नामुमकिन है- पूरे देश की तो छोड़ दें, अकेले एक राज्य में भी यह काम भगीरथ प्रयास के बराबर होगा। यह बात अलग है कि कानूनी नोटिसों और एफआइआर की इतनी भारी संख्या अपने आप में इस बात को साबित करती है कि कम से कम दो साल तक देश में डंडे का राज चला है। सुप्रीम कोर्ट दो साल के इस सर्वसत्तावाद के बाद राज्यतंत्र को जब 'ऑरवेलियन' कहने को मजबूर हुआ, तो जाहिर है ये आंकड़े उसकी नजर से भी ओझल नहीं रहे होंगे।

उपर्युक्त समस्याओं की पृष्ठभूमि में पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति ने दो बार पत्रकारों पर हमले के राष्ट्रीय आंकड़े जारी करने की योजना बनायी- 2020 के अंत में और 2021 के अंत में- लेकिन हर बार आंकड़ा संग्रहण को लेकर दरपेश हुई चुनौतियों के चलते यह काम अब तक लंबित है। अकेले उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसे आंकड़े जुटाना ही बहुत मुश्किल का काम था। जिन संस्थानों ने भारत में 2020 और 2021 में प्रेस की आजादी पर अपने आंकड़े जारी किये हैं, उनमें परस्पर फर्क स्पष्ट है। केस की

समीक्षा और चयन के उनके अपने मानक संभवत: उनका काम आसान करते हों, लेकिन CAAJ के साथ यह सुविधा नहीं है क्योंकि यहां हम इस बात को जरूरी नहीं मानते कि पत्रकार की मौत या उस पर हमला अथवा मुकदमा 'लाइन ऑफ ड्यूटी' में ही हो तो गिना जाएगा। हां, बेशक आत्महत्या और कोरोना से हुई पत्रकारों की मौतें इस रिपोर्ट के लिहाज से अपवाद हैं, इसके बावजूद ऐसी मौतों का एक सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है।

यह सर्वविदित है कि कोरोना के दौर में जिन पत्रकारों की मौत महामारी से हुई, उसमें लचर चिकित्सा व्यवस्था और राजकीय कुप्रबंधन का योगदान रहा है। लखनऊ में अकेले अप्रैल 2021 में वेंटिलेटर न मिल पाने से आधा दर्जन पत्रकारों की मौत हो गयी थी (पायनियर, 23 अप्रैल 2021)। इनमें वरिष्ठ पत्रकार विनय श्रीवास्तव की मौत पर तो काफी चर्चा हुई थी जो अपनी अंतिम सांस तक मुख्यमंत्री और अफसरों को ट्वीट करते रहे। कोविड से उत्तर प्रदेश में पहली दर्ज मौत आगरा के पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ की हुई थी। इससे कुछ दिन पहले कोविड की शुरुआत में ही बनारस की युवा पत्रकार रिज़वाना तबस्सुम ने अपनी जान दे दी थी। इस आत्महत्या के पीछे भी सामाजिक-आर्थिक कारण ही थे। कायदे से दो साल के भीतर ऐसी आत्महत्याओं और मौतों को भी प्रेस की आज़ादी से जुड़ी रिपोर्टों में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान में वर्णित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये मामले जीवन के अधिकार के हनन की श्रेणी में आते हैं।

इस रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया में आयी ऐसी तमाम चुनौतियों और अपनी सीमाओं के बावजूद समिति ने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा से उन मामलों को कवर कर लिया जाय जहां पत्रकारों को उनका काम करने से रोका गया अथवा उनके काम के चलते उन्हें प्रताड़ित किया गया। जाहिर है, प्रताड़ना के ज्यादातर मामले राजकीय हैं। मार्च 2017 से 2019 तक अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश शांत रहा, लेकिन मार्च 2020 से लेकर अब तक वह पत्रकारों की कत्लगाह में तब्दील होता दिखा है। यह वही अवधि है जब तमाम बुनियादी संवैधानिक अधिकारों को लॉकडाउन के साये में ताखे पर रख दिया गया।

प्रस्तुत रिपोर्ट चार श्रेणियों में पत्रकारों पर हुए हमले को बांटती है- हत्या, शारीरिक हमले, मुकदमे/गिरफ्तारी और हिरासत/धमकी/जासूसी। सिर्फ उन्हीं मामलों को रिपोर्ट में जगह दी गयी है जिनके प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के लिए ज्यादातर सामग्री समिति की उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से लॉकडाउन के दौरान नियमित भेजी गयी थी। इसके अलावा सीपीजे, न्यूज़लॉन्ड्री और आरआरएजी के आंकड़ों से इसे अपडेट किया गया है। तकरीबन सभी मामले मीडिया में कम या ज्यादा रिपोर्टेड हैं।

रिपोर्ट को तैयार करने में सीपीजे के भारत संवाददाता कुणाल मजूमदार, समिति के संरक्षक आनंद स्वरूप वर्मा और समिति के यूपी प्रभारी विजय विनीत का विशेष योगदान है। समिति के सदस्य शिव दास और संरक्षक संतोष गुप्ता ने उत्तर प्रदेश से नियमित हमलों के प्रकरण से अवगत करवाने का कार्यभार निभाया है। आंकड़ों के संकलन-संग्रहण और आकलन का काम समिति के सदस्य अंकुर जायसवाल ने किया है।

इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के वक्त सामने लाने के पीछे चली प्रक्रिया पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल), यूपी और पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति (CAAJ) के बीच एक संवाद का परिणाम है। पीयूसीएल, यूपी ने मानवाधिकार हनन पर राज्य के सभी राजनीतिक

दलों को एक मांगपत्र भेजा था। उस सिलसिल में हुई एक ऑनलाइन बैठक में आमंत्रण के दौरान राज्य में चुनाव के बाद एक पत्रकार सुरक्षा कानून लाने पर प्रस्ताव दिया गया था। चूंकि पीयूसीएल को छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून का मसविदा बनाने का अनुभव है, लिहाजा यह बात चली थी। उसी संदर्भ में यह तय पाया गया था कि जल्द से जल्द यूपी में पत्रकारों पर बीते पांच वर्षों में हुए हमलों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाय।

अपनी तमाम सीमाओं और कमियों के साथ यह रिपोर्ट आपके सामने है। इस रिपोर्ट का व्याख्यात्मक सार और इसका एक गुणात्मक विश्लेषण आगे के पन्नों में अलग से दिया जा रहा है। अंत में कुछ अनुलग्नक नत्थी हैं जो उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता की गंभीर स्थिति पर मुहर लगाते हैं।

पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति कोरोना महामारी का शिकार हुए देश-दुनिया के तमाम पत्रकारों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। समिति के संरक्षक मंडल के सदस्य रहे वरिष्ठ पत्रकार श्री शेष नारायण सिंह का निधन भी इसी दौर में हुआ। समिति की ओर से उन्हें सादर नमन।

अभिषेक श्रीवास्तव
पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति (CAAJ)
फरवरी, 2022

www.caajindia.org
committeeagainstassault@gmail.com
https://www.facebook.com/caajindia
https://twitter.com/caajindia

पाँच साल के आंकड़ों पर एक नज़र

उत्तर प्रदेश में 2017 से फरवरी 2022 के बीच पत्रकारों के उत्पीड़न के कुल 138 मामले पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति (CAAJ) ने दर्ज किये हैं। ये मामले वास्तविक संख्या से काफी कम हो सकते हैं। इनमें भी जो मामले ज़मीनी स्तर पर वेरिफाई हो सके हैं उन्हीं का विवरण यहां दर्ज है। जिनके विवरण दर्ज नहीं हैं उनको रिपोर्ट में जोड़े जाने का आधार मीडिया और सोशल मीडिया में आयी सूचनाएं हैं।

हमले की प्रकृति	हत्या	शारीरिक हमला	मुकदमा/गिरफ्तारी	धमकी/हिरासत/जासूसी	कुल
वर्ष					
2017	2	0	0	0	2
2018	0	1	1	0	2
2019	0	3	9	7	19
2020	7	11	32	2	52
2021	2	29	23	3	57
2022	1	4	1	0	6
कुल	12	48	66	12	**138**

जैसा कि ऊपर दी हुई तालिका से स्पष्ट है, पाँच साल के दौरान 75 फीसद से ज्यादा हमले के मामले 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के दौरान दर्ज किए गए हैं। कुल 12 पत्रकारों की हत्याओं का आंकड़ा सामने आया है, हालांकि ये कम हो सकता है। हमलों की प्रकृति के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा हमले राज्य और प्रशासन की ऑर् से किए गए हैं। ये हमले कानूनी नोटिस, एफआइआर, गिरफ़्तारी, हिरासत, जासूसी, धमकी और हिंसा के रूप में सामने आए हैं।

इन हमलों के विश्लेषण और निहितार्थ पर आगे के अध्यायों में चर्चा है। नीचे वर्ष और श्रेणी के हिसाब से नामवार तालिका देखी जा सकती है।

Assault on Journalists in Uttar Pradesh in five years (2017-till date)

Nature of Assault	Murder	Physical Assault	FIR/Arrest	Intimidation/Detention/Surveillance	Total
Year					
2017	Naveen Gupta, Rajesh Mishra				2
2018		Satyendra Gangwar	Chandan Dubey		2
2019		Amit Sharma, Khurshid Misbahi, Vijay Vinit (Sonbhadra)	Dr. Aleemullah Khan, Santosh Jaiswal, Pawan Jaiswal, Ishika Singh and Anuj Shukla, Anshul Kaushaik, Ashish Tomar, Shakil Ahmad, Bachcha Gupta	Nalini Sharma, Sumaira Khan, Santosh and Nishant, reporters and crew member of Republic TV, Omar Rashid, Seema Azad	19
2020	Rakesh Singh, Suraj Pandey, Uday Paswan, Ratan Singh, Vikram Joshi, Shubham Mani Tripathi, Faraz Ahmad (Kaushambi)	Ravi Chaudhary, Vinay Tiwari, Asad Rizwi, Naveen Singh, Ankit Singh, Krishna Kumar Singh, Manoj Kumar Soni, Shailendra Vikram Singh, Devesh Tyagi, Vishwanath (Amethi), Amarnath Jha (Kaushambi)	Siddique Kappan, Lakhan Singh, Aamir Khan, and Moin Ahmad, Sankalp Neb, Amitabh Rawat, Supriya Sharma, Ashish Awasthi, Ravindra Saxena, Mohammad Irfan, Ajay Bhadauria and Ors., Four unnamed Journalists in Bhadohi, Siddhartha Varadarajan, Vijay Vineet, and Subhash Rai, Akash Yadav+5, Hafiz Niyamat, Suresh Bahadur Singh, Dharmendra Singh and Dhara Singh (Fatehpur), Sachin Rawat, Razi Siddiqui, Sarfaraz Warsi, Vivek Mishra	Manish Pandey, Dilnawaz Pasha	52
2021	Raman Kashyap, Sulabh Srivastava	Naveen Awasthi, Krishna Tiwari, Pateshwari Singh, Awadhesh Parashar, Sarfaraz Warsi, Nitin Srivastava, Razi Siddiqui, and Fakhar-e-Alam, Santosh Kumar, Devesh Pal, Sanjiv Gupta and all four, Tushar Srivastava and Vivek Rai (LKO), Sanjay Srivastava and family, Vipin Singh (Gonda), Akash Gupta (LKO), Pratap Singh Azad, Pilibhit, Bithuna(Auraiya) and Kakvan (Kanpur)- unnamed journos attacked, Devesh Kumar Mishra (Lakhimpur), Rajnish Kumar (Hardoi), Hamirpur, Mainpuri, Women Journalist stabbed (LKO), Desh Deepak (Unnao)	Nidhi Suresh, Mohammad Zubair, Rana Ayub, Saba Naqvi, The Wire, Seraj Ali and Mukul S Chauhan, Siddharth Varadarajan and Ismat Ara, Rajdeep Sardesai, Mrinal Pande, Zafar Agha, Paresh Nath, Vinod K Jose and Anant Nath, Mohit Kashyap, Amit Singh and Yasin Ali, Manoj Shukla, Yashwant Singh, Fareed Shamsi and Ubaid-ur-Rehman, Danvir Singh	Dainik Bhaskar and Bharat Samachar, Deepak Gidwani (Pegasus)	57
2022	Sudhir Saini	Vijay Raj (Sitapur), Unnamed scribe in Kaushambi, Anand Shukla (Kunda), Journalist attacked by Akhilesh Yadav Security in Ghaziabad	Pankaj Nishad (Fatehpur)		6
Number of Journalists assaulted in Uttar Pradesh from 2017 till date					138

पत्रकारों की हत्या के मामले

2022

(1)

Date: 26 January, 2022

Location: Saharanpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Sudhir Saini, Shah Times

Brief: On 26 January 2022, journalist Sudhir Saini was on a motorbike and overtook the vehicle in which three persons were seated. Angered by this, the men stopped the journalist and beat him up. Saini was taken to a hospital, where he succumbed to injuries. Senior SP of Saharanpur, Akash Tomar, said, "Jahangir and Farman were immediately arrested by Saharanpur police in the case involving death of Sudhir Saini due to road rage incident. We will ensure that they are convicted in a fast-tracked manner."

Link: Deccan Herald

2021

(2)

Date: 3 October, 2021

Location: Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh

Name and Organization: Raman Kashyap, Sadhana News

Brief: On 3 October 2021, journalist Raman Kashyap of Sadhana News died after being allegedly crushed by a speeding car while covering the farmers' protest at a village in Lakhimpur Kheri district, Uttar Pradesh. Initially, it was claimed that the journalist was beaten by the farmers. However, the family of the deceased journalist alleged that they were under immense pressure from the police and sections of the media to say that the journalist had been beaten up by farmers. On 8 November 2021, State government of Uttar Pradesh informed the Supreme Court that journalist Raman Kashyap died of the impact of the car owned by Union Minister Ajay Mishra's son and not by lynching by farmers. On 14 December 2021, the Special Investigation Team (SIT) of the Uttar Pradesh Police probing the incident said that the incident was a pre-planned and a deliberate act, and not of negligence or callousness.

Link: Newslaundry TOI

Date: 13 June 2021

Location: Pratapgarh, Uttar Pradesh

Name and Organization: Sulabh Srivastava, ABP News

Brief: On the night of 13 June 2021, Sulabh Srivastava, a TV journalist for ABP News and ABP Ganga, was found dead under mysterious circumstances in Pratapgarh district, Uttar Pradesh. Just a day before his death, Sulabh Srivastava wrote to the Uttar Pradesh Police saying he felt threatened following his recent reportage of liquor mafias in the district. Seeking protection, Srivastava had said he had been informed by sources that the liquor mafia was angry with him after the publication of his report and wanted to harm him or his family. However, the police said that the journalist died in a "motorcycle accident." Demanding a high-level investigation, opposition political parties alleged that the journalist was killed by the liquor mafias for his reportage.

Link: Indian Express

2020

(7)

Date: 27 November, 2020

Location: Balrampur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Rakesh Singh

Brief: On 27 November 2020, Rakesh Singh (27 years), a journalist with a local newspaper, and his friend Pintu Sahu (34 years), died of burn injuries after the house of the journalist was set ablaze by a former village head identified as Ravi Chaudhary, Ram Surat and Babu Mishra at Kalwari village in Balrampur district, Uttar Pradesh. Pintu died on the spot, while the journalist died at hospital. In his dying statement, Rakesh Singh named the three accused and said that he was targeted for writing against corrupt practices of the former village head. On 3 December, PCI took suo motu cognizance and sought a report from the government of Uttar Pradesh.

Legal Status: A letter petition has been filed before the Allahabad High Court seeking suo motu action

Link: NDTV PCI Live Law

Date: 12 November, 2020

Location: Unnao, Uttar Pradesh

Name and Organization: Suraj Pandey

Brief: On 12 November 2020, the body of journalist Suraj Pandey (25 years) who worked for a local Hindi daily was found on a railway track in Unnao district, Uttar Pradesh. Police claimed that the journalist committed suicide. However, the police lodged a case on charges of murder, criminal conspiracy and criminal intimidation against some persons including two police personnel identified as Sub-Inspector Suneeta Chaurasia and Constable Amar Singh on the basis of a complaint by Suraj's mother. The complaint alleged that Suraj was killed by the accused and the body was thrown on the track to project it as suicide.

Link: Indian Express

Date: 24 August, 2020

Location: Ballia, Uttar Pradesh

Name and Organization: Ratan Singh

Brief: On the night of 24 August 2020, Ratan Singh (43 years), a journalist working for a Hindi news channel, was shot dead near his home in Ballia district, Uttar Pradesh. He was reportedly chased and shot dead by three men. According to police, the journalist was killed over a property dispute. However, the deceased's father Binod Singh rejected the claim of the police.

Chief Minister Yogi Adityanath has announced a compensation of ₹ 10 lakh for the family of the journalist. The Chief Minister "has expressed his deepest condolences and also directed that all possible action be taken against the accused," his office said in a statement.

Legal Status: All three men allegedly involved in the attack have been arrested.

Link: NDTV

Date: 16 November, 2020

Location: Sonbhadra, Uttar Pradesh

Name and Organization: Uday Paswan

Brief: On 16 November 2020, Uday Paswan, a correspondent with a Hindi daily, was beaten to death at Barwadih village under Kone police station in Sonbhadra district, Uttar Pradesh. Uday Paswan had a land dispute with the former village head identified as Keval Paswan. There had been threat to their life in connection with the land dispute since 2016 and they had been demanding police protection. However, no police protection was provided. On 16 November, Uday Paswan and his wife, Sheetla Paswan had gone to the police station to seek police protection in view of threat. While returning, the Keval Paswan and his sons had brutally beaten Uday and his wife. Uday died on the spot, while his wife succumbed to her injuries in a hospital later.

Legal Status: Superintendent of Police Sonbhadra Ashish Srivastava, said on 18 November 2020, "Inspector Kone police station, a sub-inspector and a constable have been suspended in this connection. Five of six accused persons have also been arrested while the main accused, Keval Paswan, who is also a former village head, is absconding."

Link: Indian Express

Date: 20 July, 2020

Location: Ghaziabad, Uttar Pradesh

Name and Organization: Vikram Joshi, *Jansagar Today*

Brief: On 20 July 2020, Vikram Joshi who worked for Jansagar Today was shot dead in front of his two minor daughters in Ghaziabad, Uttar Pradesh. Earlier on 16 July 2020, Vikram Joshi had submitted a complaint to the police, claiming that his niece was being sexually harassed by a group of men, including one Ravi Kumar. On 17 July, Vikram and his sister went to the office of the Senior Superintendent of Police (SSP), Ghaziabad and filed a second complaint against the group but the police did not take any action. The people against whom he had filed complaints allegedly killed him.

Legal Status: A chargesheet has been filed by the police in connection with journalist Vikram Joshi murder case in which 10 people have been booked, said Kalanidhi Naithani, Senior Superintendent of Police (SSP), Ghaziabad on 14 August.

Link: newslaundry NDTV

Date: 19 June, 2020

Location: Unnao, Uttar Pradesh

Name and Organization: Shubham Mani Tripathi, *Kampu Mail*

Brief Detail: On 19 June 2020, Shubham Mani Tripathi alias Nikk (25 years), a journalist with a Hindi daily named Kampu Mail, was shot dead by unidentified persons near Doodh Mandi in Gangaghat area in Unnao district, Uttar Pradesh. He was returning home with his friend on a motorcycle when the incident took place. Prior to his death, Shubham Mani Tripathi was threatened by a woman identified as Divya Awasthi, who dealt with land businesses and was politically connected. He had filed an FIR against her but the police did not take any action. He then in a Facebook post had expressed concern about his safety but the police did not take him seriously. On 26 June 2020, the PCI condemned the killing and sought a report from the State Government.

Legal Status: The Allahabad high court on August 16 quashed the order of detention under the National Security Act (NSA) of Kanhaiya Awasthi, an accused in the murder. The court cited the delay in the disposal of Awasthi's representation by the Unnao district magistrate as well as the Union government as the reason for quashing the detention order.

Link: Newsclick CPJ PCI Live Law

Date: 7 October, 2020

Location: Kaushambi, Uttar Pradesh

Name and Organization: Faraz Aslam, *Paigham-e-Dil*

Brief: Faraz Aslam, a journalist of a weekly newspaper, was shot lifeless by unknown folks on October 7 close to Idgah in Mahgaw city of Pooramufti police station space. After the incident, the household denied any type of enmity to the police. After almost 5 days of intensive investigation, the Puramufti police on Monday arrested Cebu alias Saifulhak, a resident of Mahgav. The police declare that the accused Sibu used to maintain a feud with the deceased Faraz. In 2019, Faraz despatched him to jail for the crime of Gokshi. After coming from jail he was on the lookout for an opportunity to kill Faraz.

Legal Status: SP Abhinandan mentioned that the arrested accused has confessed his crime.

Link: Navbharat Times, Amar Ujala

2017

(2)

Date: 30 November, 2017

Location: Kanpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Naveen Gupta, Hindustan

Brief: A 35-year-old year-old journalist, Naveen Gupta, was shot dead by unidentified assailants in Kanpur's Bilhaur on 30 November, 2017. Two men called out to the journalist as he was parking inside a complex where his brother had a garment store. After, talking with the men, Naveen Gupta walked away. Four other men standing a short distance away then shot at the journalist from across the railway line. The two people he spoke to before just stood there and did not react at all. Once Naveen was lying on the ground, one on them went to check on him and left immediately after. He died on his way to the hospital.

Legal Status: On 17 March 2018, The Mainpuri police arrested 'contract killer' Raju Baheliya for his alleged involvement in the murder of journalist Naveen Gupta.

Link: HT newslaundry TOI

Date: 21 October, 2017

Location: Ghazipur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Rajesh Mishra, Dainik Jagran

Brief: Rajesh Mishra was a stringer for the Hindi daily Dainik Jagran. Mishra was also an RSS worker. Police alleged that the murder mastermind Raju Yadav was angry about stories by Mishra that accused him of illegal sand mining and alcohol trafficking. Assailants on motorbikes shot dead Rajesh Mishra. The suspects are members of a gang headed by a man named as Raju Yadav, who is suspected of being the mastermind.

Legal Status: Three people were arrested in connection with the murder. Gang leader Raju Yadav was still absconding.

Link: Firstpost

हिंसक हमलों के उपलब्ध विवरण

2021

Date: 25 January 2021

Location: Kanpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Mohit Kashyap, K News

Amit Singh, News Nation

Yasin Ali, JMD News

Brief Detail: On 25 January 2021, three journalists identified as Mohit Kashyap, Amit Singh, and Yasin Ali were booked for publishing a 'wrong' story about children being made to perform in the cold without warm clothes. The case was registered against them on a complaint by Basic Siksha Adhikari, SunitDutt at Akbarpur police station under IPC Section 505 (statements conducing to public mischief) and Section 506 (criminal intimidation). Mohit works with TV news channel, K News, Amit works for News Nation and Yasin work with a Hindi channel JMD News.

Link: newslaundry

Date: 28 January 2021

Location: Uttar Pradesh

Name and Organization: Rajdeep Sardesai, Mrinal Pande, Zafar Agha, Paresh Nath,

Vinod K Jose and Anant Nath

Brief Detail: On 28 January 2021, police in Uttar Pradesh registered an FIR against six prominent journalists - Rajdeep Sardesai, Mrinal Pande, Zafar Agha, Paresh Nath, Vinod K Jose and Anant Nath under various charges including sedition, for allegedly spreading misinformation on the death of a farmer during farmers' tractor rally in Delhi on 26 January 2021. The FIR, lodged at Noida Sector 20 police station, invoked 11 IPC sections, including Section 124A (sedition), 153-A

(promoting enmity between groups), section 295A (deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings), Section 504 (intentional insult), Section 506 (criminal intimidation) and Section 120B (criminal conspiracy to commit offence punishable by death).

Legal Status: On 9 February 2021, the Supreme Court stayed the arrest of the six prominent journalists - journalists Rajdeep Sardesai, Mrinal Pande, Zafar Agha, Paresh Nath, Vinod K Jose and Anant Nath along with others in the case.

Link: Indian Express The News Minute

Date: 1 February 2021

Location: Rampur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Siddharth Varadarajan and Ismat Ara, The Wire

Brief Detail: On 30 January 2021, an FIR was lodged against Siddharth Varadarajan, editor of news website The Wire, at Civil Lines police station in Rampur, Uttar Pradesh for posting on Twitter a report on the death of a protester in New Delhi during the Republic Day incidents. The FIR was registered on the complaint by one Sanju Turaiha under IPC sections 153B (imputations, assertions prejudicial to national integration) and 505(2) (statements creating or promoting enmity between classes).

A day after the Uttar Pradesh Police filed an FIR against The Wire's founding editor Siddharth Varadarajan, The Wire and its reporter Ismat Ara have also been added to the FIR during the investigation.

The case was registered at the Civil Lines police station of Rampur district against Varadarajan for a tweet which shared an article written by Ara, published by The Wire on January 30. The article shared claims made by the family of a protester who died during the farmers' tractor rally on Republic Day.

The complaint alleges that Varadarajan's tweet and Ara's article have "led to anger among the common people in Rampur and has given rise to tension." A tweet by Rampur district magistrate, replying to Varadarajan's tweet, also said, "Hope you understand your story could cause law and order problem here. It has already caused tensed situation here (sic)."

Legal Status: On 7 November 2021, The Allahabad High Court granted interim protection from arrest to The Wire's founding editor Siddharth Varadarajan and reporter Ismat Ara.

Link: Indian Express The Wire Live Law

Date: 12 March 2021

Location: Moradabad, Uttar Pradesh

Name and Organization: Awadhesh Parashar

Brief Detail: On 12 March 2021, journalist Awadhesh Parashar was allegedly thrashed by party workers of Samajwadi party during a press conference in Moradabad, Uttar Pradesh. On the complaint of the journalist, an FIR was registered at Pakhwara police station against several workers of Samajwadi Party including the chief of the party Akhilesh Yadav. The alleged assault took place when the journalist asked questions about Azam Khan to the former Uttar Pradesh chief minister.

Link: TOI

Date: 5 April, 2021

Location: Lucknow, Uttar Pradesh

Name and Organization: Cameraman, ANI

Brief Detail: In April 2021, Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh used abusive language against an Asian News International (ANI) cameraman during a bite on COVID vaccination. The video of the same was widely shared in public domain.

Link: Vartha Bharati newslaundry

Date: May – June, 2021

Location: Barabanki, Uttar Pradesh

Name and Organization: Seraj Ali and Mukul S Chauhan, The wire

Brief Detail: In June 2021, an FIR was registered against online news portal, The Wire and two of its journalists identified as Seraj Ali and Mukul S Chauhan in Barabanki, Uttar Pradesh. The FIR was registered for allegedly spreading animosity in society and disturbing communal harmony

over its video documentary on the demolition of a “mosque” by district administration, Barabanki in May 2021. Two others identified as Mohammad Naeem and Mohammad Anees were also named in the FIR. The Wire called charges “baseless” and accused the BJP government of “criminalising the work of journalists who are reporting what is happening in the state” The complaint was lodged by a police officer based on which the FIR was registered under IPC sections 153 (wantonly giving provocation with intent to cause riot), 153-A (promoting enmity between different groups), 505 (1) (b) (with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public), 120-B (criminal conspiracy) and 34 (acts done by several persons in furtherance of common intention).

Link: Indian Express

Date: 15 June 2021

Location: Loni, Uttar Pradesh

Name and Organization: Mohammad Zubair, Rana Ayub, Sabi Naqvi, The Wire, Twitter

Brief Detail: On 15 June 2021, the Uttar Pradesh police filed an FIR against AltNews journalist Mohammad Zubair, journalist Rana Ayub, media organisation The Wire, Congress’s Salman Nizami, Maskoor Usmani and Shama Mohamed, writer Saba Naqvi and social media giant Twitter INC (Indian National Congress) and Twitter Communications India at the Loni Border police station. The FIR was filed at late night at 11.20 pm based on a complaint by police Sub-Inspector Naresh Singh after a video of an elderly Muslim man alleging assault in Ghaziabad, Uttar Pradesh went viral on social media. The police booked the journalists and others in connection with tweets on the case. The police invoked Section 153 (provocation for rioting), 153A (promoting enmity between different groups), 295A (acts intended to outrage religious feelings), 505 (mischief), 120B (criminal conspiracy) and 34 (common intention) of the IPC against them. The elderly Muslim man identified as Abdul Samad (72 years) was attacked in Loni on 5 June 2021. The attackers also cut off his beard as seen in the viral video. Samad lodged an FIR against unidentified persons on 7 June 2021. In his viral video, the man alleged that he was forced to chant Jai Shri Ram by the assailants, and that he was attacked because of his religion. However, the police later in their clarification said that it was an interpersonal matter and the attackers had beaten him up because he had given them a taveez (amulet) that they believe caused their family member’s miscarriage. In the FIR, it was stated that despite this clarification by the police, the accused did not delete their tweets, nor did Twitter make any efforts to delete them.

Link: The Wire

Date: 29 June 2021

Location: Ayodhya, Uttar Pradesh

Name and Organization: Pateshwari Singh

Brief Detail: On 29 June 2021, Pateshwari Singh, a freelance journalist from Uttar Pradesh, was knocked off his motorcycle by a vehicle and hit on the head with iron rods by five men after he had written about lack of development in the Ayodhya constituency of a BJP legislator. Singh, who writes for newspapers and web portals, was admitted to the district hospital in Ayodhya with serious injuries to the back of his skull. The injured journalist said he had written some articles about the alleged lack of development in the constituency of Gosainganj MLA Indra Pratap Tiwari alias Kahbbo Tiwari, and he had alleged that Tiwari's henchmen had been threatening him with dire consequences for his articles. However, the MLA denied any involvement in the attack on the journalist. Police registered a case against unidentified persons for attacking the journalist and started an investigation.

Link: Telegraph

Date: 7 July, 2021

Location: Shahjahanpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Nidhi Suresh, Newslaundry

Brief Detail: In July 2021, Nidhi Suresh, a journalist with Newslaundry, was booked for defamation by the Uttar Pradesh police based on a complaint by News18 journalist Deep Srivatsava. According to Newslaundry, the FIR was registered by Sadar Bazar police in Shahjahanpur district for a tweet put out by Nidhi. However, the FIR did not mention which tweet of Nidhi was allegedly defamatory. The FIR was registered under Sections 500 (punishment for defamation) and 501 (printing or engraving matter known to be defamatory) of the IPC. However, criminal defamation is a non-cognizable offence as per the Code of Criminal Procedure (CrPC). This means that the police cannot register an FIR based on a criminal defamation complaint made directly by the complainant. The police is authorised to register an FIR only based on the direction of a judicial magistrate under section 200 of the CrPC. In other words, a complainant must approach a magistrate for criminal defamation complaints. According to Newslaundry, Nidhi had received a call on the morning of 5 July 2021 from the Investigating Officer asking her to record her statement in Shahjahanpur. Later in the day, she received another call asking her to make an

in-person oral and written statement despite Nidhi saying she was in Delhi. Pertinently, the FIR was registered after Nidhi had reported on the case of Ayesha Alvi, a Hindu woman who had recently converted to Islam. Ayesha had moved the Delhi High Court alleging that she had been harassed by the media for her conversion to Islam. In her petition, Ayesha had listed one mobile number alleging that she had received a threat call from the individual, who extorted Rs 20,000 from her. When Nidhi had contacted the number, the caller identified himself as Deep Srivastava, a reporter with News18. However, Deep denied the allegations that he had extorted money from Ayesha.

Link: The News Minute

Date: 10 July, 2021

Location: Unnao, Uttar Pradesh

Name and Organization: Krishna Tiwari

Brief Detail: On 10 July 2021, journalist Krishna Tiwari was allegedly beaten up by Chief Development Officer (CDO) Divyanshu Patel and some workers of Bharatiya Janta Party (BJP) in the Bangarmau area in Miyaganj in Unnao district, Uttar Pradesh. Tiwari had gone to report from a polling centre in the Bangarmau area for the block panchayat chief polls being held across the State. Tiwari alleged that the CDO continued to beat him despite knowing him. He also alleged beaten up by a local BJP leader and workers. In a video widely circulated on social media, the CDO was seen chasing down the journalist in public and beating him viciously. The CDO, who is an Indian Administrative Service (IAS) officer, was accused of attacking the journalist because "he was filmed by the latter allegedly helping kidnap local council members to stop them from voting".

Link: The Quint NDTV

Date: 22 July 2021

Location: Lucknow, Uttar Pradesh

Name and Organization: Dainik Bhaskar and Bharat Samachar

Brief Detail: : On 22 July 2021, the Income Tax Department conducted raids at the offices of leading newspaper Dainik Bhaskar as well as a Lucknow based news channel, Bharat Samachar. The raids were conducted at over 30 locations of Dainik Bhaskar in Delhi, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. The homes and offices of the group's promoters were also raided. Bharat Samachar's offices in Lucknow and the home of its editor were also searched. The raids were conducted for alleged tax evasion. However, Dainik Bhaskar Editor Om Gaur stated that raids were a surprise and an attempt to suppress independent journalism. The raids were conducted against the backdrop of some very critical coverage by both the news organisations on government's handling of the pandemic.

Link: NDTV

Date: 15 December, 2021

Location: Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh

Name and Organization: Naveen Awasthi, ABP News

Brief Detail: On 15 December 2021, Union Minister of State for Home Ajay Mishra allegedly used abusive language against journalists by calling them "thieves" and pushed one of them identified as Naveen Awasthi, TV journalist with ABP News when they sought his comment on the Uttar Pradesh Police Special Investigation Team (SIT) charging his jailed son Ashish under additional IPC sections in connection with the 3 October 2021 violence in Lakhimpur Kheri. Naveen Awasthi was allegedly pushed by the Union Minister and another TV reporter's mobile phone was snatched by him and not returned. The journalist speaking to media said *"There was inauguration by minister Ajay Mishra Teni today. Several journalists were there. I asked him about the oxygen plant, which he inaugurated, and after that, I asked him about the additional charges against his son. When I asked him about it, he got angry and started using abusive language. He snatched my microphone and tried to take my mobile phone. He took the mobile phone of a fellow TV reporter, which has not been returned. He chased the journalist to beat him up. We left the venue from a side exit."*

Link: Indian Express

2020

Date: 26 March, 2020

Location: Varanasi, Uttar Pradesh

Name and Organization: Vijay Vineet and Subhash Rai, *Jansandesh Times*

Brief Detail: On 26 March 2020, the District Magistrate (DM) of Varanasi, Uttar Pradesh sent a show-cause notice to journalist Vijay Vineet and Editor-in-Chief Subhash Rai of Jansandesh Times after the newspaper carried a story that members of the Musahar community, a Dalit sub-caste, were surviving on grass at Koiripur village in the district due to COVID-19 lockdown. The village fell under Prime Minister Narendra Modi's parliamentary constituency of Varanasi. The report was accompanied by photographs of children eating grass. In the notice, DM stated that he had got the matter investigated by an Additional District Magistrate-level officer and found that the report was fabricated one. The DM claimed that the Dalit children were not eating grass but ankari dal (wild pulses) that grow along with wheat in the fields. The notice asked the newspaper to refute its story in the next edition on 27 March 2020 failing which an inquiry shall be initiated against them. But journalist Vijay Vineet stood by his report. On 10 July 2020, the PCI took suo motu cognizance and called for comments from the state government of Uttar Pradesh

Link: The Print PCI

Date: 1 April, 2020

Location: Uttar Pradesh

Name and Organization: Siddharth Vardarajan

Brief Detail: On 1 April 2020, the Uttar Pradesh Police registered an FIR against Siddharth Varadarajan, one of the founding editors of news website, The Wire, under Sections 188 and 505(2) of the IPC for reporting that State Chief Minister Adityanath had attended a public religious event in Ayodhya on 25 March 2020 after the Prime Minister had announced a national lockdown to deal with the Coronavirus. The FIR was filed in Faizabad based on the complaint of an individual.

Legal Status: Justice Chandra Dhari Singh of the Allahabad High Court allowed anticipatory bail to Varadarajan after finding that there were reasonable grounds for his apprehension of arrest.

Singh said if Varadarajan is arrested, he may be released on bail on furnishing a personal bond of Rs 2 lakh, along with two sureties of equal amount. The court also rejected the Uttar Pradesh government's submission that Varadarajan may flee abroad as he has an American passport.

Link: The Hindu Scroll.in Indian Kanoon

Date: 13 April, 2020

Location: Bhadohi, Uttar Pradesh

Name and Organization: Four unnamed journalists

Brief Detail: On 13 April 2020, an FIR was registered at Gopiganj police station in Bhadohi district, Uttar Pradesh against four journalists for reporting that a woman had thrown her five children into a river because of lockdown-induced hunger. The FIR only mentioned editors and reporters from news agency Indo-Asian News Service (IANS) and Business Insider without naming them.

Legal Status: The four journalists were booked under sections 505(1)(b) and 188 of the IPC.59 On 10 July 2020, the Press Council of India (PCI) took suo motu cognizance and called for comments from the Uttar Pradesh government regarding registration of FIR against the four journalists.

Link: RRAG The Quint PCI

Date: 30 April, 2020

Location: Lucknow, Uttar Pradesh

Name and Organization: Manish Pandey, *News1 India*

Brief Detail: On 30 April 2020, Manish Pandey of News1 India, a Hindi news channel, was summoned (without serving a notice) before the Special Task Force headquarters in Lucknow, Uttar Pradesh by Assistant Superintendent of Police, Vishal Vikram Singh. On 1 May 2020, Singh interrogated Pandey for nearly an hour regarding the source who leaked an official letter published by Pandey. On 17 April 2020, Pandey broke the story of a letter sent by the Directorate General of Medical Education and Training, Uttar Pradesh to bureaucrats in the State's medical education department. The letter said that the PPE kits supplied to eight hospitals and medical colleges in the State did not meet the required quality standards.

Manish says, “Congress leader Priyanka Gandhi and Samajwadi Party Chief tweeted about his victimization that saved me from jail but the bureaucratic pressures compelled me to resign.”

“Even today I am suffering displeasure of the officers after exposing reality of ‘Namammi Gange’ project in Kanpur contrary to CM Yogi’s claims,” he asserted.

Link: newslaundry tehelka

Date: 13 May, 2020

Location: Fatehpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Ajay Bhadauria

Brief Detail: On 13 May 2020, an FIR was registered against journalist Ajay Bhadauria (57 years) for a tweet in which he pointed out that a community kitchen was closed down at Vijaypur in Fatehpur district, Uttar Pradesh. The police booked him for circulating false news based on a complaint by the SDM.

On June 7, about a dozen journalists in Uttar Pradesh’s Fatehpur jumped into the Ganga river, half naked, to conduct a “jal satyagraha”, a protest against the harassment meted out by the local administration for their purported critical reporting.

In a press note released on 7 June 2020, the Fatehpur District Magistrate claimed that Bhadauria, who has been a journalist for 32 years, “is not associated with any print or electronic media in the year 2020” and accused Bhadauria of using “his personal Twitter account to besmirch the administration by tweeting one-sided, delusional rumours.”

Link: newslaundry

Date: 14 May, 2020

Location: Uttar Pradesh

Name and Organization: Mohammed Irfan, Jansandesh Times

Brief Detail: On 14 May 2020, Mohammed Irfan, a journalist with Jansadesh Times, was allegedly harassed, arrested and jailed for taking photographs at a Covid-19 screening centre for migrants

set up at Harua block in Varanasi district, Uttar Pradesh. He was sent to Baragaon police station by the district officials, where he was allegedly questioned for two hours, photographs on his phone deleted and charged under Section 151 of the Code of Criminal Procedure.

Legal Status: The journalist secured bail on 12 June 2020.

Link: Caravan

Date: 18 May, 2020

Location: Sitapur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Ravindra Saxena, *Today-24*

Brief Detail: On 18 May 2020, an FIR was registered against Ravindra Saxena, a journalist with Today-24 news portal, for reporting mismanagement at a quarantine centre in Sitapur district, Uttar Pradesh. In a video report, Saxena spoke to people at a quarantine centre in Maholi tehsil in the district, who alleged that they were served rotten rice. The FIR was registered on the complaint of district administration filed through a Scheduled Caste employee at the SDM office accusing the journalist of violating the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and the Disaster Management Act. On 9 November, 2020 Editors Guild of India has sent a letter to the Chief Minister of UP, on protection of press freedom and journalists' rights. Including journalist's case

Link: The Wire Indian Kanoon EGI

Date: May, 2020

Location: Lucknow, Uttar Pradesh

Name and Organization: Aashish Avasthi

Brief Detail: In May 2020, an FIR was lodged against Aashish Avasthi, editor of Media Break, for a report regarding problems being faced by Home Guards in Uttar Pradesh during COVID-19. On 20 May 2020, the PCI sought a report from the State Government with respect to the FIR.

Link: PCI Business Standard

Date: 13 June, 2020

Location: Varanasi, Uttar Pradesh

Name and Organization: Supriya Sharma, *Scroll.in*

Brief Detail: On 13 June 2020, the Uttar Pradesh police registered an FIR against Supriya Sharma, Executive Editor of Scroll.in on the basis of a complaint by Mala Devi, who Sharma had quoted in a report titled 'In Varanasi village adopted by Prime Minister Modi, people went hungry during the lockdown', published on Scroll.in on 8 June 2020. Scroll.in had interviewed Mala Devi at Domari village in Varanasi on 5 June 2020, but she alleged that the journalist had misreported her and filed an FIR. 82 The FIR was registered under sections 269 and 501 of the IPC and sections 3(1)(d) and 3(1)(r) of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act.

The Editors Guild of India, the Committee to Protect Journalists, Network of Women in Media, India, Delhi Union of Journalists and Brihanmumbai Union of Journalists also criticised the action.

Legal Status: On 26 August, 2020, The Allahabad High Court said that the investigation in the case would continue and Sharma's plea to quash the FIR could not be accepted at the current stage.

Link: The Wire Scroll.in

Date: 22 June, 2020

Location: Kanpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Ankit Singh, *Hindi Khabar*

Brief Detail: On 22 June 2020, Ankit Singh, a reporter working for Hindi Khabar, was allegedly assaulted by the police when he was doing a story on a shelter home where 57 girls were found to be COVID-19 positive at Swaroop Nagar in Kanpur, Uttar Pradesh. When his colleague, Shubham Shukla, tried to shoot the beating on his phone, the police snatched away the phone.

Link: The Week

Date: 23 June, 2020

Location: Kanpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Unnamed media institutions

Brief Detail: On 23 June 2020, an FIR was filed against unnamed media institutions on publication of news item about Government Girl Shelter Home, Kanpur, Uttar Pradesh where 57 girls were infected with COVID-19. The FIR lodged at Swarup Nagar police station in Kanpur district accused the media institutions of spreading fake news and booked under Sections 188, 505 and 288 IPC, Section 23 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, Section 74 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Section 3 of the Epidemic Diseases Act.86 On 25 June 2020, the PCI took suo-motu cognizance on the FIR lodged against unknown media institutions and called for a report from the Government of Uttar Pradesh.

Link: The Hindu PCI

Date: August, 2020

Location: Deoria, Uttar Pradesh

Name and Organization: Amitabh Rawat

Brief Detail: In August 2020, an FIR was registered against journalist Amitabh Rawat for allegedly maligning the image of the State Government of Uttar Pradesh after he shared in social media a video of a minor girl cleaning the floor in the female ward of the District Hospital, Deoria. He was booked under Sections 506, 504, 389, and 385 of the IPC and Section 67 of the Information Technology Act.

Legal Status: On 30 September, 2020, Allahabad High court said on the petition to quash the FIR – "After having heard learned counsel for the parties and perusing the impugned FIR as well as the other material brought on record, it cannot be said that prima facie no offence is made out against the petitioner. Therefore, the prayer for quashing the FIR is refused.

However, we dispose of this writ petition with the direction that investigation of the aforesaid case shall go on but the petitioner shall not be arrested in the aforesaid case till the submission of police report under Section 173(2) Cr.P.C., subject to his cooperation during investigation."

Link: Newsclick Indian Kanoon

Date: 4 August, 2020

Location: Saharanpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Sankalp Neb

Brief Detail: On 4 August 2020, journalist Sankalp Neb was booked in Saharanpur, Uttar Pradesh for allegedly sharing an unverified post on Twitter about the administration's handling of Covid-19. The FIR was registered under provisions of the Epidemic Diseases Act and the Information Technology Act based on a complaint by Chief Medical Officer, Saharanpur. Neb said that he had merely re- posted another person's allegations in the form of a screenshot and alleged that he was targeted for reports that were not in favour of the administration.

Link: Indian Express

Date: 26 August, 2020

Location: Meerut, Uttar Pradesh

Name and Organization: Naveen Singh

Brief Detail: On the night of 26 August 2020, journalist Naveen Singh and his family members were attacked allegedly by a leader of the Bahujan Samaj Party (BSP) and two others at Jagriti Vihar colony in Meerut district, Uttar Pradesh. According to Singh, he received a call from BSP leader named Raviraj and when he went out of his house, Raviraj started hitting him. Soon, Prince Yadav and Anshu Yadav, who lived in the neighborhood, helped Raviraj in assaulting Singh. When the journalist's elder brother Avinash tried to intervene the attackers also hit him on his head.

Legal Status: Rajvir had been arrested and other 2 accused were absconding.

Link: News18

Date: 7 September, 2020

Location: Bijnor, Uttar Pradesh

Name and Organization: Ashish Tomar

Shakil Ahmed

Lakhan Singh

Aamir Khan

Moin Ahmad

Brief Detail: On 7 September 2020, the police booked five journalists identified as Ashish Tomar, Shakil Ahmed, Lakhan Singh, Aamir Khan and Moin Ahmad after they reported that a Dalit family was allegedly prevented from drawing water from a hand pump by some people at Basi village in Bijnor district, Uttar Pradesh. Cases were filed under Sections 153A (promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony), 268 (public nuisance) and 503 (criminal intimidation) of the IPC and Section 66A of the Information Technology Act. The FIR had charged Ashish Tomar and Shakil Ahmed of trying to vitiate social amity by circulating fake news. The journalists stood by their story and the district administration had to take back the case after an action committee of journalists lodged a protest.

The Editors Guild has written to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, urging him to address the issue of press freedom and ensure the rights and safety of journalists working in the state. The letter, dated 9 November, noted that there had been several incidents in the state that raised concern over the freedom of independent journalism in Uttar Pradesh.

Legal Status: On 20 October 2020 Bijnor district court has refused to take cognizance of a police chargesheet filed against five local journalists on the ground that there is “insufficient evidence” against them.

Link: Indian Express EGI (9 November 2020)

Date: 2 October, 2020

Location: Lucknow, Uttar Pradesh

Name and Organization: Asad Rizvi

Brief Detail: On 2 October 2020, journalist Asad Rizvi, associated with The Wire and other media houses, was attacked by the police when he was covering a protest by the Samajwadi Party at

Hazratganj in Lucknow, Uttar Pradesh over the Hathras gang-rape and murder of a Dalit girl. The police snatched his mobile phone, hit with lathis (sticks) and he was briefly detained. Before releasing him, the police warned him not to public the incident.

Link: UNI

Date: 5 October, 2020

Location: Mathura, Uttar Pradesh

Name and Organization: Siddique Kappan

Brief Detail: Siddique Kappan (41 years), Secretary of the Kerala Union of Working Journalists (KUWJ) and working with Malayalam news websites like *AZHIMUKHAM.COM*, was arrested by Uttar Pradesh Police from a toll plaza in Mathura while he was going to Hathras to meet the kin of the deceased Dalit woman who was killed after gang rape by four upper-caste men in September 2020.

Legal Status: Kappan was booked under the UAPA and charged with sedition for alleged links with the Popular Front of India and its students' organisation, Campus Front of India. He was denied bail and continued to be in jail at the year's end.

Link: Scroll.in

Date: 7 November, 2020

Location: Lalitpur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Vinay Tiwari, *Bundelkhand Times TV*

Brief Detail: On 7 November 2020, journalist Vinay Tiwari (40 years) was allegedly beaten up with sticks by a village head identified as Babita Mishra and her sons, Vivek Mishra, Abhishek Mishra and Aryan Mishra at Dhaura village in Lalitpur district, Uttar Pradesh. The attack took place when Vinay Tiwari, who works for a local news channel, Bundelkhand Times TV, when he was taking photographs of MGNREGA work done by machines instead of labourers. The journalist's mobile phone, motorcycle and cash were also taken away.

Legal Status: An FIR was lodged against the four accused under Sections 394 (voluntarily causing hurt in committing robbery), 307 (attempt to murder), 323 (voluntarily causing hurt), 504

(Intentional insult with intent to provoke breach of the peace) and 506 (criminal intimidation) of the IPC.

Link: Indian Express

Date: 7 December, 2020

Location: Ghaziabad, Uttar Pradesh

Name and Organization: Ravi Choudhary, *PTI*

Brief Detail: On 7 December 2020, Press Trust of India (PTI) photojournalist Ravi Choudhary was allegedly attacked by 5-6 men in Ganga Canal Road in Ghaziabad, Uttar Pradesh. The journalist alleged that the attackers came in a BOLERO car (No: UP 14 DN 9545) with "bharat sarkar" written on it. He further alleged that Muradnagar police refused to lodge FIR. Choudhary's photograph of a farmer being beaten by a police officer during the farmers' protest had gone viral some days prior to the attack on him.

Link: newslaundry

2019

Date: 12 February, 2019

Location: Aligarh, UP

Name and Organization: Nalini Sharma, Sumaira Khan, Santosh and Nishant, reporters and crew member of Republic TV

Brief Details: The journalists got into a scuffle with the students of Aligarh Muslim University (AMU) while covering an event on Tuesday, 12 February. The students allege that one of the reporters called AMU the "University of Terrorists" during the live coverage; the reporters allege that they were attacked only because they were from Republic TV. The journalists were reportedly there to cover an event of small, sidelined political parties and marginalised activists to discuss the government's failures and achievements.

Legal Status: Fourteen students of Aligarh Muslim University in Uttar Pradesh were booked for sedition on 13th February after clashes that followed a confrontation with journalists from news channel Republic TV. The police filed a First Information Report against the students based on a complaint by Bharatiya Janata Party Yuva Morcha district leader Mukesh Lodhi.

Link: Youtube Scroll.in

Date: 10 June, 2019

Location: Noida, Uttar Pradesh

Name and Organization: Ishika Singh and Anuj Shukla

Brief Detail: On 10 June, 2019 Ishika Singh, head of a private television news channel and its editor Anuj Shukla were remanded in 14-days judicial custody for allegedly broadcasting defamatory content against Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath.

During a debate on the Noida-based news channel on June 6, a woman had allegedly made defamatory statements against Adityanath, according to officials. Workers affiliated to a political party had approached the police with a complaint against the news channel for broadcasting the claims of the woman without verifying facts, the officials said.

A case was registered against the channel officials at Phase 3 police station under Indian Penal Code sections 501 (printing or engraving matter known to be defamatory), 153 (promoting enmity between different groups), 505 [1] (Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report), 505 [2] (statements conducing to public mischief), the police said.

Legal Status: On 25 July, 2019, The Allahabad High Court grandted bail to Ishika Singh and Anuj Shukla.

Link: New Indian Express TOI

Date: 12 June, 2019

Location: Shamali, UP

Name and Organization: Amit Sharma reporter of news channel News 24

Brief Details: Amit Sharma, the News 24 correspondent beaten up in Uttar Pradesh's Shamli by a Government Railway Police (GRP) officer on 12th June night has alleged that the assault was vengeance for a news report that caused him to lose over Rs 1 lakh in illegal proceeds every month. Amit said "I had been on his (Shamli railway station house officer Rakesh Kumar Upadhyay's) radar for the past few months as I had done a story against him for supporting an illegal vendor racket run by a person named Nafees in trains and stations." According to Sharma, who was subsequently taken to the police station and allegedly kept under illegal detention, Upadhyay even urinated on his face and into his mouth.

Legal Status: Moradabad DIG (railways) Subhash Chandra Dubey said Rakesh Kumar Upadhyay and the constable, Sanjay Kumar, had been suspended. "I'm investigating the matter myself and will take strictest action possible."

Link: The Print newslaundry

Date: 31 August, 2019

Location: Mirzapur, Uttar Pradesh

Name and Organization: Pawan Jaiswal

Brief Detail: Police have filed four criminal cases against Pawan Kumar Jaiswal for filing a video report that showed a school in Mirzapur district serve children only “roti” (or Indian bread) with salt. In the cases filed by the authorities, they accuse Jaiswal of defaming the state government. local officials accused Jaiswal and his source Rajkumar Pal under various sections of the Indian Penal Code including sections 120 B (criminal conspiracy), 186 (voluntarily obstructing public servants in discharge of his functions), 193 (false evidence) and 420 (cheating) on August 31.

Legal Status: The Uttar Pradesh police has given a clean chit to Pawan on 19 December, 2019

Link: Aljazeera The Print

Date: 4 September, 2019

Location: Azamgarh, Uttar Pradesh

Name and Organization: Santosh Jaiswal

Brief Detail: On 4 September 2020, journalist Santosh Jaiswal was arrested on false charges of extortion and obstructing public servants from discharging their duty after he took photographs of some children mopping the floor at Oodpur primary school in Azamgarh district, Uttar Pradesh. The police took both the journalist and the school principal, Radhey Shyam Yadav to the police station, where the school principal lodged a complaint against Jaiswal alleging that he came to the school and ordered some school children to mop the floor and took their photographs.

Link: The Wire

Date: 18 December, 2019

Location: Aliganj, Lucknow

Name and Organization: Dr. Aleemullah Khan, Qaumi Raftar

Brief Details: Founder editor of Urdu newspaper Qaumi Raftar, Dr. Aleemullah Khan was detained and taken in custody for more than a day by the Lucknow police in Aliganj police station. In his first-person account he wrote that SHO Fareed Ahmed called him mastermind of riots for calling a peaceful protest against CAA in Lucknow and taken into custody. Even I wasn’t allowed

to ask for a blanket from my home in that cold night. They charged me under IT Act 153 and 67 and I got to know about this only after when I was taken to the court.

Link: newslaundry

Date: 19 December, 2019

Location: Sambhal, UP

Name and Organization: Unknown

Brief Details: The protest in Uttar Pradesh's Sambal turned violent on 19th December as protesters set state transport buses on fire. Several media persons were also attacked during the protest against the Citizenship Amendment Act. Press association of India issued a statement mentioning this incident and said, The Association is anguished over such incidents and demands speedy investigation to deter perpetrators of such crimes.

Link: India Today TOI

Date: 20 December, 2019

Location: Lucknow, UP

Name and Organization: Omar Rashid, The Hindu

Details: Omar Rashid, a journalist with The Hindu said in his first-person account; Around 6:45 pm on Friday evening, I was trying to grab a quick meal at a dhaba outside the Uttar Pradesh BJP office, waiting to hear about a press conference to be held by the UP government a few blocks away, when at least four men in plainclothes barged in. I was accompanied by Robin Verma, a local activist and friend, and two others, both journalists. The men did not identify themselves and inquired about us using strong and aggressive language. They told me they wanted to question me about something. At the very first instance, I revealed my identity as a journalist and asked them what the matter was all about. However, they packed the two of us, Robin Verma and me, into a police jeep, snatched my mobile phone and asked me to not call or inform anyone or I would regret it. They refused to explain anything to me and asked me to talk only when they asked.

They drove us to the Hazratganj police station a km away, where we were told a senior police officer wanted to talk to us. We were then escorted to a room — it looked like a cyber-cell — where within seconds of entering, cops, already stationed there, started thrashing Robin with a thick leather belt and slapped him many times.

They locked the room and asked me to keep silent when I protested why I was brought there. The policemen threatened me they would book me under 120B of the Indian Penal Code if I didn't keep quiet and also said they had evidence to show I was part of the arsonists who vandalized police property and engaged in violence during the protest against the Citizenship Amendment Act. I again clarified that I am a journalist and showed them my identity cards. One of them knew me as a journalist but that obviously was not considered.

They responded by abusing me and said I should keep my journalism to myself, in abusive Hindi. My Kashmiri background was referred to several times and despite informing them about my newspaper, they continued with their questions and threats. “You are a suspect,” I was told and asked to shut up.

For the next few minutes, the policemen badly beat up Robin Verma. They made the same charges against him. We were then packed into the rear seat of a police jeep and driven a few km away to the Sultanpuri police outpost without being told anything.

Here too, we were taken into a tiny room and questioned. The cops repeatedly asked me about the whereabouts of some “Kashmiris” and where I was hiding them. I replied to all their questions in the negative as I had no clue why I was brought there in the first place. A few minutes later, two policemen, of the rank of CO, came in.

I was told to stand up. The police officer, whose name I don't know, told me he would set me right. He was wearing protective gear.

I was then taken to another room in the quarters of a constable, where I was also photographed like a suspect.

The same cop, who threatened to put me in place, again asked me about the “Kashmiris” and said he would tear out all my beard and thrash me if I didn't answer his questions as per his liking. Since I didn't have my phone, I could not note down the long list of expletives used against me. He left after some time and I was kept in the room till around 8:30 pm. I was then called to the office of the Circle Officer of Hazratganj who questioned me for a few more minutes. I was asked the same questions I was asked earlier: if I was a part of the protest, if I knew certain individuals, especially Kashmiris and about my professional and background. I informed them that I was indeed present during the protests, as a journalist covering it. The CO asked me if I felt regret at the violence during the protests and refused to believe me when I did. He also lectured me on the "hypocrisy" of Leftist ideology and heavily criticised China and its clampdown on citizens.

By then, the information had reached the CMO.

The same cops who abused and intimidated me earlier now apologised to me and tried to explain that I was picked up due to a “confusion.” This was despite the fact that I had identified myself as a journalist from the very first moment. The police then let me off.

Link: The Hindu

Date: 20 December, 2019

Location: Meerut, UP

Name and Organization: Khurshid Misbahi, reporter of ETV Bharat

Brief Details: Khurshid Misbahi, a reporter with ETV Bharat was attacked by rioters in Meerut, UP. In his first-person account he wrote in a Facebook post - "I am a reporter with ETV Bharat. On 20th December, I was covering the riots in Meerut. When I was taking some visuals of burning bikes and a police chowki then 3 to 4 rioters came and attacked me on my head by iron rod and bricks. I have severe injuries on my head. They snatched my office mobile, camera stick, microphone, ID and helmet."

Link: Facebook

2018

Date: 26 June, 2018

Location: Pilibhit, Uttar Pradesh

Name and Organization: Satyendra Gangwar

Brief Details: Satyendra Gangwar, a journalist, was assaulted and shot at by Aman Jaiswal and his aide on June 24 in Uttar Pradesh's Bisalpur. The Times of India reported that a first information report (FIR) was filed by Gangwar's brother, Jitendra. Jaiswal had allegedly fired at Satyendra near the railway station, hitting the journalist in the left leg and lower back, Times of India reported. Jitendra was quoted by Times of India as telling the Pilibhit superintendent of police (SP) Balendu Bhushan Singh, “Jaiswal is a part of the mining mafia, who grabs contracts for the food department’s procurement centres in the district during the Rabi and Kharif seasons every year. He is extremely well- connected politically. In order to appease ministers and MLAs, he extorts money from rice millers."

Link: newslaundry TOI

Date: 18 December, 2018

Location: Sonbhadra, Uttar Pradesh

Name and Organization: Chandan Dubey

Brief Detail: In December, A local Journalist from Anpara of Sonbhadara district of Uttar Pradesh uploaded a video on YouTube covering the issues of contract workers of the Hindalco Industries limited. In his detailed coverage he highlighted the problems of workers who are on strike for five months. No other local or national media outlet covered on this issue. After few days he was brutally beaten by the police in Anpara. Police charged him under strong sections of IPC. It is said that the management of the Hindalco industries Ltd. was not happy with his reporting.

Link: Youtube Media Vigil

2017

Date: 11 January, 2017

Location: Mathura, Uttar Pradesh

Name and Organization: Unknown

Brief Detail: An 'objectionable video' posted on the social media group of the district PRO cell in Mathura has led the Uttar Pradesh police to interrogate a journalist, even as investigations are on to confirm the authenticity of the clip. Ajay Yadav, PRO of the Senior Superintendent of Police told PTI that the video was posted by a journalist in the WhatsApp group of Mathura district PRO cell between 11.27 AM and 12.46 PM yesterday. The video purportedly appeals to the people or WhatsApp users to forward it as much as possible, so that it gets the Prime Minister's attention.

Police has issued a notice in cognizance of the video message, stating that without a confirmtory evidence, one party cannot condemn or defame another. A legal action would be taken if some person or group is found guilty in this connection, as per the police notice.

However, the person under police scanner has claimed that he had just recieved the message and had forwarded it in the group.

Link: janta ka reporter

व्याख्यात्मक रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्ष के दौरान प्रेस की आज़ादी पर हुए हमलों पर केंद्रित इस रिपोर्ट को हमलों की प्रकृति के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है: (1) हत्या, (2) शारीरिक हमला, (3) मुकदमे/गिरफ्तारी और (4) हिरासत/धमकी/जासूसी। सभी श्रेणियों को मिलाकर पांच साल में पत्रकारों पर हमले के कम से कम 138 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमले 2020 और 2021 में हुए हैं।

2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से लेकर इस रिपोर्ट के प्रकाशन तक राज्य में कुल 12 पत्रकारों की हत्या हुई है। सबसे ज्यादा सात पत्रकार 2020 में मारे गये। 2018 और 2019 में एक भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई। जिस साल राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, 2017 में दो पत्रकार मारे गये- कानपुर के बिल्हौर में हिंदुस्तान अखबार के नितिन गुप्ता और ग़ाज़ीपुर में दैनिक जागरण के प्रतिनिधि राजेश मिश्रा। पत्रकारों पर हमले के विरुद्ध समिति (CAAJ) ने सितंबर 2018 में दिल्ली में आयोजित अपने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर में मारे गए जिन पत्रकारों की गवाहियां करवायी थीं, उनमें नितिन गुप्ता के परिजन भी शामिल थे। आज नितिन गुप्ता के छोटे भाई खुद पत्रकारिता कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर एक चैनल चला रहे हैं। राजेश मिश्रा की हत्या को शुरुआत में संदिग्ध माना गया था क्योंकि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी थे। 2018 में प्रकाशित अपनी पहली रिपोर्ट में CAAJ ने राजेश मिश्रा का केस शामिल नहीं किया था क्योंकि उस वक्त तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। बाद में ग़ाज़ीपुर की पत्रकार यूनियन सहित और क्षेत्रीय पत्रकार संघों ने इस मामले को उठाया। कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने काफी बाद में इस मामले में ज़मीन पर जाकर पड़ताल की और राजेश मिश्रा को अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में जगह दी, जिसके आधार पर CAAJ ने भी इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है।

पत्रकारों की हत्या

2017	नवीन गुप्ता, राजेश मिश्रा
2018	
2019	
2020	राकेश सिंह, सूरज पांडे, उदय पासवान, रतन सिंह, विक्रम जोशी, शुभम मणि त्रिपाठी, फराज़ असलम
2021	सुलभ श्रीवास्तव, रमन कश्यप
2022	सुधीर सैनी
कुल	**12**

दो साल के अंतराल के बाद 2020 में कुल सात पत्रकार राज्य में मारे गये- राकेश सिंह, सूरज पांडे, उदय पासवान, रतन सिंह, विक्रम जोशी, फराज़ असलम और शुभम मणि त्रिपाठी। राकेश सिंह का केस कई जगह राकेश सिंह 'निर्भीक' के नाम से भी रिपोर्ट हुआ है। बलरामपुर में उन्हें घर में आग लगाकर दबंगों

ने मार डाला। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पड़ताल बताती है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के चलते उनकी जान ली गयी। राकेश सिंह राष्ट्रीय स्वरूप अखबार से जुड़े थे। उन्नाव के शुभम मणि त्रिपाठी भी रेत माफिया के खिलाफ लिख रहे थे और उन्हें धमकियां मिली थीं। उन्होंने पुलिस में सुरक्षा की गुहार भी लगायी थी लेकिन उन्हें गोली मार दी गयी। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को भी दिनदहाड़े गोली मारी गयी। इसी साल बलिया के फेफना में टीवी पत्रकार रतन सिंह को भी गोली मारी गयी। सोनभद्र के बरवाडीह गांव में पत्रकार उदय पासवान और उनकी पत्नी की हत्या पीट-पीट के दबंगों ने कर दी। उन्नाव में अंग्रेजी के पत्रकार सूरज पांडे की लाश रेल की पटरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुई थी। पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया लेकिन परिवार ने हत्या बताते हुए एक महिला सब-इंस्पेक्टर और एक पुरुष कांस्टेबल पर आरोप लगाया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। कौशांबी में फराज असलम की हत्या 7 अक्टूबर 2020 को हुई। फराज़ पैगाम-ए-दिल में संवाददाता थे। इस मामले में पुलिस को मुखबिरी के शक में हत्या की आशंका जतायी गयी है क्योंकि असलम पत्रकार होने के साथ-साथ पुलिस मित्र भी थे। इस हत्या के ज्यादा विवरण उपलब्ध नहीं हैं। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया था उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया जिसके मुताबिक उसने असलम को इसलिए मारा क्योंकि वह उसके अवैध धंधों की सूचना पुलिस तक पहुंचाते थे। ज्यादातर मामलों में हुई गिरफ्तारियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि मामला हत्या का था।

2021 में दो पत्रकारों की हत्या यूपी में हुई। दोनों मामले चर्चित रहे। प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव ने अपनी हत्या से पहले अर्जी देकर आशंका जाहिर की थी कि शराब माफिया उन्हें मरवा सकता है। उन्होंने स्थानीय शराब माफिया के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। पुलिस ने चेतावनी पर कार्रवाई करने के बजाय हत्या को सामान्य हादसा ठहरा दिया। इस मसले पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बाकायदे एक बयान जारी करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया था (देखें अनुलग्नक)। दूसरी हत्या लखीमपुर खीरी में रमन कश्यप की थी जिसका आरोप केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर है, जिसने अपनी गाड़ी से कथित रूप से प्रदर्शनरत किसानों को रौंद दिया था जिसमें कश्यप भी शिकार हुए थे। इस मामले में एक अखिल भारतीय जांच टीम जिसमें पीयूसीएल भी शामिल था, उसने निष्कर्ष दिया कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की गयी हत्या है। (देखें अनुलग्नक)

इस साल की शुरुआत सहारनपुर में एक पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या से हुई है। सैनी को गाड़ी ओवरटेक करने के मामले में कथित तौर पर सरेराह दिनदहाड़े पीट-पीट कर मार डाला गया। इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है या नहीं।

शरीरिक हमलों की सूची बहुत लंबी है। कम से कम 50 पत्रकारों पर पांच साल के दौरान शारीरिक हमला किया गया, जो इस रिपोर्ट में दर्ज है। इसमें जानलेवा हमले से लेकर हलकी-फुलकी झड़प भी शामिल है। हमलावरों में पुलिस से लेकर नेता और दबंग व सामान्य लोग शामिल हैं। ज्यादातर हमले रिपोर्टिंग के दौरान किये गगे। सबसे भयावह तीनों मामले 2019 में शामली जिले में न्यूज 24 के पत्रकार अमित शर्मा, ईटीवी भारत के खुर्शीद मिसबाही और सोनभद्र के विजय विनीत से जुड़े हैं। खुर्शीद और अमित शर्मा के केस CAAJ की पिछली रिपोर्ट में शामिल हैं। 2018 का सत्येंद्र गंगवार का केस भी CAAJ की सितंबर 2018 में प्रकाशित पहली रिपोर्ट में विस्तार से शामिल था। सोनभद्र में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन (यूपीडब्लूजेयू) के जिलाध्यक्ष विजय विनीत पर कातिलाना हमला नवंबर 2019 में हुआ था। हमलावर एक हिस्ट्रीशीटर है जो अब तक 110 बार पाबंद हो चुका था। उसने विजय विनीत पर अवैध कब्जे और

आपराधिक हरकतों का विरोध करने पर बुरी तरह से मारपीट कर हाथ तोड़ दिया। विनीत दैनिक जागरण में रह चुके हैं और हमले के वक्त भाजपा विधायक भूपेश चौबे के मीडिया प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे।

पत्रकारों पर शारीरिक हमले के मामले में संख्या 2020 में काफी बढ़ी है और 2021 सबसे ज्यादा हमलों का गवाह रहा है। इस रिपोर्ट में शारीरिक हमलों की श्रेणी में दर्ज केवल वे मामले हैं जिनमें मुकदमा कायम नहीं किया गया। मुकदमे वाली श्रेणी में भी कई मामले ऐसे हैं जिनमें मारपीट और झड़प देखने में आया। इनमें सबसे चर्चित दो मामले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मियों के साथ पत्रकारों की हुई धक्कामुक्की के रहे। पहले मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआइआर दर्ज करवायी गयी थी। इन हमलों में इकलौता मामला जो महिला पत्रकार से जुड़ा था, वह सितंबर 2021 का है जब लखनऊ में एक दलित महिला पत्रकार मुस्कान कुमारी को चाकू से मारा गया था।

गंभीर हमलों में एक मामला सीतापुर से 2020 का है। सीतापुर जिले में न्यूज़ एजेंसी "शार्प मीडिया" के मान्यता प्राप्त पत्रकार शैलेन्द्र विक्रम सिंह 9 अगस्त को अवैध रूप से संचालित हो रहे एक अस्पताल की कवरेज करने पहुंचे थे। वहां के झोलाछाप डॉक्टर और उसके साथियों ने उसे बुरी तरह पीटा जिससे पत्रकार को सिर में गंभीर चोटें आयी थीं। पत्रकार ने जैसे-तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचायी और थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसी तरह मुरादनगर में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर रवि चौधरी पर जानलेवा हमला दिसंबर 2020 में हुआ। इसी तरह सितंबर में सहारनपुर के एक पत्रकार देवेश त्यागी पर दिनदहाड़े सरेराह गंभीर हमला हुआ, जिसका आरोप एक स्थानी भाजपा नेता पर है। उक्त मामले में भाजपा नेता सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी।

नवंबर 2020 मे सोनभद्र में मनोज कुमार सोनी पर हुआ हमला बहुत जानलेवा रहा। उनके ऊपर यह दूसरी बार हुआ हमला था। इससे पहले 2018 में वे हमले का शिकार हो चुके हैं। दैनिक परफेक्ट मिशन में काम करने वाले मनोज के ऊपर लोहे की रॉड से छह लोगों ने 4 नवंबर को हमला किया था जिसमें उनकी कई हड्यिां टूट गयी थीं। सीपीजे के मुताबिक अपना इलाज करवाने में उन्हें ढाई लाख का खर्च आया था। अगर पुलिस ने 2018 में उन पर हुए हमले के बाद कार्रवाई की होती तो यह नौबत नहीं आती।

2021 में हमलों की संख्या भले ज्यादा है लेकिन ज्यादातर मामले पुलिस उत्पीड़न से जुड़े हैं। 2022 में अब तक अमेठी, कौशाम्बी, कुंडा, सीतापुर, गाजियाबाद से पत्रकारों पर शारीरिक के मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर का स्रोत सोशल मीडिया और स्थानीय अखबारों में प्रकाशित सूचनाएं हैं जिनकी जमीनी पुष्टि नहीं हो सकी है।

हत्या के बाद यदि संख्या और गंभीरता के मामले में देखें तो कानूनी मुकदमों और नोटिस के मामले 2020 और 2021 में खासकर सबसे संगीन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा होगा जहां पत्रकारों को खबर करने के बदले मुकदमा न झेलना पड़ा हो। जरूरी नहीं कि खबर बहुत बड़ी और खोजी ही हो- सामान्य चिकित्सीय लापरवाही की खबर से लेकर क्वारंटीन सेंटर के कुप्रबंधन और पीपीई किट की अनुपलब्धता जैसे मामूली मामलों पर भी सरकार की ओर से एफआइआर दर्ज की गयी हैं। मिड डे मील नमक रोटी परोसे जाने, लॉकडाउन में मुसहर समुदाय के बच्चों के घास खाने से लेकर स्कूल में बच्चों से पोछा लगवाने जैसी खबरों पर बाकायदा प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाते हुए मुकदमे किये गये।

स्कूली बच्चों को घटिया भोजन परोसे जाने के मामले में पुलिस आंचलिक पत्रकार पवन जायसवाल के पीछे तब तक पड़ी रही, जब तक भारतीय प्रेस काउंसिल ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। योगी सरकार की ज्यादती यहीं नहीं रुकी। सरकार ने दैनिक जनसंदेश का विज्ञापन भी रोक दिया जहां यह खबर प्रकाशित हुई थी। इस घटना के कुछ ही दिन बाद आज़मगढ़ जनपद के आंचलिक पत्रकार संतोष जायसवाल को 7 सितंबर 2019 को एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से जबरदस्ती परिसर की सफाई कराये जाने का मामला उजागर करने पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।

इस रिपोर्ट में महत्वपूण्र योगदान देने वाले CAAJ के यूपी प्रभारी विजय विनीत ने ऐसे मामलों पर न्यूजक्लिक में एक विस्तृत रिपोर्ट की है जिसमें वे लिखते हैं:

"कोविड काल में लॉकडाउन के दौरान बिगड़े हुए हालात पर रिपोर्ट करने के कारण उत्तर प्रदेश में कम से कम 55 पत्रकारों और संपादकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ अथवा उन्हें गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को तोपने के लिए नौकरशाही ने काफी तेजी दिखायी है और कुछ ही महीनों में कई सारे ऐसे मामले सामने आये जहां प्रशासन पर सवाल उठाने वाली खबरों के कारण पत्रकारों पर एफआइआर दर्ज की गयी। साल 2020 में लॉकडाउन शुरू होते ही मार्च के अंतिम दिनों में भूख से बेहाल मुसहर समुदाय के लोगों की हालात पर रिपोर्ट लिखने पर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने इस लेखक के लिए कानूनी नोटिस भिजवाया और गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। यही नहीं, अपने बेटे के साथ अंकरी घास खाते हुए मीडिया और सोशल मीडिया में तस्वीरें भी वायरल की। घास को दाल बताते हुए उन्होंने फर्जी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए ताना-बाना तक बुन डाला। यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से सटे वाराणसी के कोइरीपुर गांव की है, जहां मुसहर समुदाय के लोग घास खाने को मजबूर हो गये थे। इस मामले में नौकरशाही की कलई खुलने लगी तो खुन्नस निकालने के लिए पत्रकार मोहम्मद इरफान को अकारण शांतिभंग में गिरफ्तार लिया गया। साथ ही विजय सिंह नामक पत्रकार को सरेराह गोदौलिया (बनारस) चौराहे पर पीटा गया और बाद में हवालात में डाल दिया गया।"

उत्तर प्रदेश में खबरों को सरकारी काम में बाधा बताने और झूठ साबित करने के लिए केवल आंचलिक और क्षेत्रीय पत्रकारों को ही निशाना नहीं बनाया गया। इसमें बड़े पत्रकार भी लपेट लिए गये। सबसे दिलचस्प मामला स्क्रोल डॉट इन की संपादक सुप्रिया शर्मा का रहा। यह भी प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र बनारस का ही केस है। वाराणसी जिला प्रशासन ने दबाव बनाकर सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) कानून 1989 और आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कराया। वाराणसी के रामनगर थाने में डोमरी गांव की माला देवी से शिकायत दर्ज करवायी गयी कि सुप्रिया शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में गलत तरीके से बताया है कि कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के कारण आपातकालीन भोजन की व्यवस्था न होने से उनकी स्थिति और खराब हुई है। सुप्रिया ने डोमरी गांव के लोगों की स्थिति की जानकारी दी थी और गांव वालों के हवाले से बताया था कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से उनकी स्थिति और बिगड़ गयी है। डोमरी उन गांवों में से एक है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। सुप्रिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के फेल हो जाने से गांव के गरीब लोगों को जरूरी राशन के बिना गुजारा करना पड़ रहा है। शर्मा पर यह एफआईआर

भी कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की स्थिति पर रिपोर्ट करने, स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने और चुप कराने की कोशिश थी।

लॉकडाउन में प्रशासनिक कुप्रबंधन को छुपाने के लिए न केवल मुकदमे किये गये बल्कि वरिष्ठ पत्रकारों के परिवारों को भी निशाना बनाया गया। एक गंभी मामला जो चर्चा में नहीं आ सका वो उरई से चलने वाले यंग भारत न्यूज़ पोर्टल के संपादक संजय श्रीवास्तव से जुड़ा है जो 35 वर्ष तक बड़े अखबारों में ब्यूरो प्रमुख के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने प्रशासन में काफी ऊपर तक अपने साथ हुए अन्याय की गुहार लगायी है लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। श्रीवास्तव की दिसंबर 2021 में लिखी एक अर्जी के अंश:

"मेरे द्वारा सच्ची और निष्पक्ष खबरों के प्रकाशन के क्रम में पिछले सप्ताह 'कैसे आया प्रशासन बैकफुट पर' नामक शीर्षक से एक समाचार यंग भारत पर प्रसारित किया गया था। इसे DM प्रियंका निरंजन ने अपनी तौहीन माना और तानाशाही रवैये के फलस्वरूप दिनांक 1 दिसंबर को हमारे पैतृक निवास 20, कृष्णा नगर उरई में बिना किसी वारंट अथवा न्यायिक आदेश के लगभग दो दर्जन बदतमीज पुलिसकर्मी कोतवाल उरई नागेंद्र कुमार पाठक के नेतृत्व में हमारे निवास के अंदर जबरन घुस आए तथा उन्होंने बदतमीजी पूर्ण ढंग से खूब धमकाया, महिलाओं से बदतमीज़ी करी। सरकारी छोटी बंदूक अड़ाकर परिजनों को धमकी दी कि प्रशासन से टकराने की अगर हिम्मत करी तो परिणाम गंभीर होंगे और सबको उठाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेज देंगे। तब तक पड़ोसी आ गये और पुलिस आलमारी में रखे 600 रुपये-सौ-सौ के 6 नोट एवं एक सोने का टूटा हुआ बाला उठाकर भाग गये। दिनांक 2 दिसंबर को पुलिस ने अपने कहे अनुसार मेरे (संजय श्रीवास्तव) और मेरे दोनों भाइयों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही लागू कर दी जो पत्रकार और पत्रकार परिवार तथा शरीफ समाज का बेहद उत्पीड़न है।"

फतेहपुर में बिलकुल इसी तरह एक वरिष्ठ पत्रकार और जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष अजय भदौरिया के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए चलायी जाने वाली कम्युनिटी किचन बंद होने की खबर लिखने के लिए भदौरिया व अन्य के खिलाफ जिला प्रशासन ने आइपीसी की धारा 505, 385, 188, 270 व 269 के तहत जून 2020 में मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120बी भी लगा दी गयी थी। एफआइआर में पत्रकार पर आरोप लगाया गया कि सामुदायिक रसोईघर बंद होने की खबर से अव्यवस्था फैल गयी।

इस घटना से आक्रोशित होकर फतेहपुर के पत्रकार जल सत्याग्रह पर चले गये। यह उत्तर प्रदेश में अपने किस्म का एक अनूठा आंदोलन रहा जब जिला प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों ने गंगा नदी में आधा पैठकर प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने लगभग दो घंटे नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे भी वापस लेने की मांग की। इस पर प्रशासन का जवाब यह आया कि फतेहपुर के डीएम ने 7 जून, 2020 को जारी एक प्रेस नोट में कहा कि जिला सूचना अधिकारी द्वारा की गयी जांच में पता चला है कि बीते 32 साल से पत्रकारिता कर रहे अजय भदौरिया साल 2020 में किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक

मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं। यह एक आधिकारिक खंडन है कि भदौरिया पत्रकार हैं। इसके बाद जल सत्याग्रह कर रहे पत्रकारों की तस्वीर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट की।

खबर को सरकारी काम में दखल और षडयंत्र मानने से लेकर अब पत्रकार को पत्रकार न मानने तक बात आ पहुंची है। यह परिघटना भी केवल स्थानीय पत्रकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में बीबीसी और हिंदू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के पत्रकारों के साथ भी यही बरताव किया जाता है। दि हिंदू के यूपी ब्यूरो ओमर राशिद का मामला बड़े विस्तार से CAAJ ने अपनी पिछली रिपोर्ट में छापा था। ऐसा ही कुछ बीबीसी के संवाददाता दिलनवाज़ पाशा के साथ घटा जब वे संभल में अपने एक रिश्तेदार को हिरासत में लिए जाने की दरयाफ्त करने थाने पहुंचे थे। दिलनवाज़ ने इस घटना के बारे में अपने फेसबुक पर लिखा था:

“मैंने अपने बारे में अपने साथ उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में हुई घटना से जुड़ी कई पोस्ट पढ़ी हैं। मैं वहां पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए निजी हैसियत से गया था। मैंने अपना परिचय बीबीसी पत्रकार के तौर पर नहीं दिया था। थाने में ये पूछते ही कि संबंधित व्यक्ति को किस कारण या किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने मेरे फोन छीन लिए और मुझे वहीं बैठने को मजबूर किया। कई बार मांगने पर भी मेरे फोन नहीं दिए गए और मेरे साथ बदसलूकी की। बाद में जब मेरे पहचान पत्र से मेरी पत्रकार के तौर पर पहचान पुलिस को पता चली तो सब माफी मांगने लगे। संभल के पुलिस अधीक्षक को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे बात की और जोर दिया कि मैं संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊं। यूपी पुलिस और प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारियों ने भी मुझसे संपर्क करके जोर दिया कि मैं शिकायत दर्ज कराऊं, लेकिन मैंने इस संबंध में कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया।"

जिन पत्रकारों पर इन पांच वर्षों में यूपी में मुकदमे दर्ज किये गये हैं उनमें 2021 की सूची हाइ प्रोफाइल है। सिद्धार्थ वरदराजन, मृणाल पांडे, राणा अयूब, ज़फ़र आगा, सबा नक़वी, विनोद के. जोस, अनंत नाथ जैसे दिल्ली के बड़े नामों को योगी सरकार ने अलग-अलग बहानों से मुकदमों में फंसाने की कोशिश की। दि वायर को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर छापे मरवाये गये।

26 जनवरी, 2021 को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव को लेकर एक एफआइआर दर्ज की गयी। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जफर आगा और अनंत नाथ सहित कुल सात जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ राजद्रोह का केस लगा दिया गया। इन सभी लोगों पर मीडिया पर पोस्ट के जरिये दंगा भड़काने, हिंसा फैलाने को लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-20 थाने में एफआइआर दर्ज की गयी।

थाने में बुलाकर पूछताछ, हिरासत, आदि की घटनाएं भी इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। जासूसी के मामले में उत्तर प्रदेश से जो पत्रकार पेगासस की जद में आये हैं, उनमें डीएनए लखनऊ के पूर्व पत्रकार दीपक गिडवानी और इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका 'दस्तक नये समय की' की संपादक सीमा आज़ाद हैं।

महामारी अधिनियम और धारा 188 के तहत उत्तर प्रदेश में इतने पत्रकारों को पुलिस द्वारा नोटिस थमाया जा चुका है कि जिसकी गिनती करना आसान नहीं है। कोविड के दौर में लगे दो लॉकडाउन के दौरान जिला और प्रखंड स्तर पर पत्रकारों पर हुए मुकदमों के सारे आंकड़े अब तक नहीं प्राप्त हो सके हैं। कुल मिलाकर हमले की सभी श्रेणियों में पांच वर्ष के दौरान जो कुल 138 मामले इस रिपोर्ट में दर्ज हैं, वे वास्तविकता से काफी कम हैं। कोशिश यही की गयी है कि चर्चित मामलों के अलावा स्थानीय स्तर पर दबे रह गए उत्पीड़न के मामलों को भी सामने लाया जाय।

यह सूची अब भी अद्यतन हो रही है। उम्मीद की जाती है कि CAAJ की 2020-2021 की समग्र राष्ट्रीय रिपोर्ट आने तक उत्तर प्रदेश में हमलों की कवरेज और सघन हो पाएगी।

रिपोर्ट के निहितार्थ और निष्कर्ष

जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है, बीते पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमलों की सघनता कोरोना महामारी के कारण लगाये गये लॉकडाउन की शुरुआत से देखने में आयी जो अब तक जारी है। सभी श्रेणियों में हमले के कुल 138 प्रकरणों में अकेले 107 मामले 2020 और 2021 को मिलाकर हैं यानी केवल महामारी के ये दो वर्ष 78 फीसदी हमलों के लिए जिम्मेदार रहे।

2019 में कुल हमलों (19) से अचानक 2020 में 250 गुना उछाल देखा गया। यह उछाल 2021 में मामूली बढ़ोतरी के साथ जारी रहा। 2017 और 2018 में केवल दो-दो केस से तुलना करें तो करीब हजार गुना उछाल दिखायी देता है। प्रेस की आजादी में 2019 से आये इस अभूतपूर्व उछाल को कैसे समझा जाय?

राजनीतिक परिस्थितियां इस परिघटना के केंद्र में हैं। 2019 की जितनी भी घटनाएं रिपोर्ट में गिनवायी गयी हैं उनमें ज्यादातर साल के अंत के आसपास की हैं जब संशोधित नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन देश में जोर पकड़ चुका था। दिल्ली के जामिया मिलिया से शुरू हुए आंदोलन की अनुगूंज उत्तर प्रदेश में आज़मगढ़ से लेकर अलीगढ़ तक बराबर सुनायी दे रही थी। इस आंदोलन को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ पुलिस और इलाकाई लोगों की बदसलूकी की खबरें आ रही थीं। यह पहला ऐसा मौका रहा जब पत्रकारों को उनका धर्म और उनका आइडी कार्ड देखकर बख्शा जा रहा था। लखनऊ के ओमर राशिद और खुर्शीद मिस्बाही का मामला ऐसा ही रहा, जिसके बारे में विस्तार से CAAJ की मार्च 2020 में प्रकाशित 'रिपब्लिक इन पेरिल' रिपोर्ट में ज़िक्र है।

यह आंदोलन हालांकि अल्पजीवी था लिहाजा यह परिघटना तीन से चार महीने चली, फिर ध्रुवीकरण शांत हुआ तो धर्म और बैनर के आधार पर पत्रकारों की खुली शिनाख्त भी बंद हो गयी। इस बीच हालांकि दो ऐसे मामले 2019 में सामने आए थे जो भविष्य में पत्रकार उत्पीड़न के ट्रेंड की आहट दे रहे थे। दो मामले तो एक ही अखबार जनसंदेश टाइम्स के पत्रकारों से जुड़े थे- पवन जायसवाल और संतोष जायसवाल। एक और मामला बच्चा गुप्ता का था। इन तीनों मामलों में समान रूप से यह पाया गया था कि खबर दिखाने पर इनके खिलाफ षडयंत्र का आरोप लगाते हुए मुकदमे किये गये। तीनों मामले बनारस और उसके आसपास के हैं। यह शुरुआत थी जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों की नियमित कवरेज को झूठा और षडयंत्रकारी बताने की और बदले में उनके ऊपर मुकदमा लादने की एक ऐसी परिपाटी शुरू हुई जिसका उत्कर्ष हमें 2020 में यूपी के कोने-कोने में देखने को मिलता है।

इस परिघटना को निम्न चरणों में बांटकर समझा जा सकता है। पत्रकार द्वारा अपनी आंखों के सामने घट रहे अन्याय, मसलन मिड डे मील में नमक रोटी (पवन जायसवाल), बच्चों द्वारा स्कूल की सफाई (संतोष जायसवाल) और बाढ़ग्रस्त थाने में कीचड़ की सफाई (बच्चा गुप्ता) की खबर या तस्वीर प्रकाशित करने पर प्रशासन का तय रवैया कुछ यूं रहता है:

1) सबसे पहले सरकारी प्रेस नोट में खबर को अफवाह और झूठ बताया जाय;
2) फिर अधिकारियों की मार्फत खबर को माहौल बिगाड़ने वाला, सौहार्द खराब करने वाला और सरकार को बदनाम करने वाला बताया जाय;

3) इसके बाद पत्रकार को नोटिस भेजा जाय;
4) पत्रकार और संपादक पर मुकदमा कायम किया जाय।

सामान्य तौर पर यह मुकदमा सरकारी काम में बाधा डालने, अफवाह फैलाने (आजकल प्रशासन ऐसी खबरों को फेक न्यूज़ कहने लगा है), सौहार्द बिगाड़ने, प्रशासन और सरकार को बदनाम करने, आदि की धाराओं में किया जाता है जिसमें महामारी अधिनियम आदि बोनस में नत्थी होते हैं। यह मामला देशद्रोह तक जा सकता है जिसमें जानबूझ कर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाकर पत्रकार को जेल में डाला जा सकता है। बनारस में दैनिक भास्कर के पत्रकार आकाश यादव के साथ यही काम एक निजी पार्टी ने पुलिस के साथ मिलकर किया। आकाश यादव ने खबर की थी कि एक निजी अस्पताल को एक अयोग्य डॉक्टर चला रहा है। उन्होंने अपनी खबर में निजी स्वास्थ्य माफिया और पुलिस की साठगांठ को उजागर किया था। बदले में आकाश यादव सहित पांच और पत्रकारों पर डकैती व यौन उत्पीडन का मुकदमा ठोंक दिया गया। इसी तरह मिर्जापुर में हिंदुस्तान अखबार के कृष्ण कुमार सिंह पर हिंसक हमला हुआ। वे पार्किंग माफिया के खिलाफ खबर लिख रहे थे। उनकी बुरी तरह पिटाई की गयी। जब वे थाने में शिकायत करने पहुंचे तो उनकी तहरीर लेने में छह घंटे से ज्यादा समय लगाया गया।

पूर्वांचल से कइ किलोमीटर दूर नोएडा में भी यही फॉर्मूला प्रशासन ने अपनाया जबकि नोएडा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अभिजात्य हिस्सा है जहां से ज्यादातर राष्ट्रीय टीवी चैनल प्रसारण करते हैं। यहां नेशन लाइव नाम के एक टीवी चैनल से इशिका सिंह और अनुज शुक्ला को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने हिंसा भडकाने की कोशिश की है और मुख्यमंत्री की मानहानि की है। बाद में चैनल के प्रमुख अंशुल कौशिक की भी गिरफ्तारी हुई। तीनों को अंततः ज़मानत तो मिल गयी लेकिन चैनल बंद करवा दिया गया यह कह कर कि उसके परिचालन के लिए मालिकान के पास पर्याप्त सरकारी मंजूरी नहीं है।

यह परिपाटी उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक 2019 में आजमायी जा रही थी। खबर दिखाने का मतलब प्रशासन को बदनाम करना स्थापित किया जा रहा था जो देश को बदनाम करने और अंततः मुख्यमंत्री को बदनाम करने तक आ चुका था। कुल मिलाकर संदेश यह दिया जा रहा था कि नियमित पत्रकारिता का कर्म दरअसल देशद्रोह की श्रेणी में आ सकता है; देश का मतलब है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का मतलब है स्थानीय प्रशासन। इस तरह देश, नौकरशाह और नेता को एक कर दिया गया था। इसे साबित करने का कार्यभार जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी के सिर पर था कि पत्रकार की खबर कैसे देशद्रोह हो सकती है। जिलाधिकारी इस मामले मे दो कदम आगे बढ़कर काम कर रहे थे। बनारस के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का मामला इस संदर्भ में दिलचस्प है जिन्होंने यह साबित करने के लिए कि लॉकडाउन से उपजी भुखमरी में मुसहरों द्वारा खायी गयी घास जंगली नहीं थी, खुद अपने छोटे से बच्चे के साथ वह घास खाते हुए फेसबुक पर एक फोटो डाल दी और बदले में भुखमरी की खबर लिखने वाले पत्रकारों को नोटिस भेज दिया।

2020 और 2021 में धड़ल्ले से इस फॉर्मूले को पूरे राज्य में लागू किया गया और राजद्रोह की धाराओं में बहुत से पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किये गये। एक पत्रकार के लिए अपनी नौकरी बजाना यानी सामान्य खबर करना भी मुश्किल हो गया। कब कौन सी खबर को सरकार झूठा बताकर उसमें साजिश सूंघ ले और केस कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसके बावजूद कुछ पत्रकारों और संस्थानों ने हार नहीं मानी। खासकर भारत समाचार और दैनिक भास्कर ने विशेष रूप से लॉकडाउन में सरकारी कुप्रबंधन और मौतों पर अच्छी कवरेज की। उन्हें इसकी कीमत छापे से चुकानी पड़ी।

सरकारी मुकदमों के बोझ तले दबी पत्रकारिता की आज स्थिति यह हो चली है कि पत्रकारों के उत्पीड़न पर पत्रकार खुद पीड़ित पत्रकार का पक्ष नहीं लेते हैं बल्कि पुलिस के बयान के आधार पर खबर लिख देते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण गाजियाबाद से समाचार पोर्टल चलाने वाले पत्रकार अजय प्रकाश मिश्र का है जिनके ऊपर चुनाव कवरेज के दौरान 7 फरवरी 2022 को उत्तराखंड के उधमसिंहनगर में एक आरटीओ अधिकारी ने एफआइआर करवायी है। सड़क पर व्यावसायिक नंबर वाले वाहनों को रुकवा कर चुनावी ड्यूटी में लगाने जैसी सामान्य घटना मुकदमे तक कैसे पहुंच गयी इसे समझना हो तो स्थानीय अखबारों में अगले दिन छपी खबर को देखा जा सकता है जिसमें पत्रकारों को पत्रकार तक नहीं लिखा गया है, बल्कि 'तीन व्यक्ति' और 'दबंग' लिखा गया है। हिंदुस्तान, अमर उजाला और दैनिक जागरण तीनों की खबरों ने लिखा है कि तीन व्यक्तियों ने परिवहन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया।

प्रशासनिक-राजनीतिक संस्कृति के मामले में उत्तराखंड का तराई उत्तर प्रदेश से कुछ खास अलग नहीं है, इसलिए यह घटना वहां नहीं तो यूपी में कहीं और भी ऐसे ही होती। आशय यह है कि बीते दो साल में रेगुलर पत्रकारीय कर्म की स्पेस को इतना संकुचित कर दिया गया है कि संस्थाओं में काम करने वाले पत्रकार भी अब घटनाओं को प्रशासन की नजर से देखने और लिखने लगे हैं, यह जानते हुए कि वह सफेद झूठ होगा। ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल पत्रकारों की नाजुक स्थिति को समझना मुश्किल नहीं है, जो अकेले अब तक 'जस देखा तस लेखा' की नीति पर काम कर रहे हैं।

इस संदर्भ में 2021 में केंद्र सरकार द्वारा लाये गये सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। सरकार के नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 के प्रावधान इस प्रकार से बनाये गये हैं कि असहमति और विरोध के स्वरों को सहजता से कुचला जा सके। ऐसा लगता है कि इन नियमों के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया से जुड़े मसलों पर निर्णय लेने की अदालती शक्तियां कार्यपालिका के पास पहुंच चुकी हैं और सरकार के चहेते नौकरशाह डिजिटल मीडिया कंटेंट के बारे में फैसला देने लगेंगे। गौर से देखें तो बीते महीनों में ऐसा ही हुआ भी है। समसामयिक विषयों पर आधारित कोई भी प्रकाशन न केवल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होता है बल्कि यह नागरिक के सूचना प्राप्त करने के अधिकार और भिन्न-भिन्न विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत होने के अधिकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। कार्यपालिका को न्यूज़ पोर्टल्स पर प्रकाशित सामग्री के विषय में निर्णय लेने का पूर्ण और एकमात्र अधिकार मिल जाना संविधानसम्मत नहीं है, लेकिन यह काम तो अघोषित रूप से बीते दो साल से हो ही रहा था। अब कार्यपालिका को एक कानून की आड़ मिल गयी है जिसका सहारा लेकर वह किसी भी खबर को मानहानिपूर्ण बता सकती है और किसी भी पत्रकार को गैर-पत्रकार साबित कर सकती है।

पत्रकार उत्पीड़न के हालिया मामलों में जिलाधिकारियों और जिला स्तर के छोटे अफसरों तक की मनमानी को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्नाव की एक घटना सतह के नीचे चल रही स्थितियों को बहुत साफ़ दिखाती है। यहां 10 जुलाई, 2021 को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को कवर कर रहे एक पत्रकार कृष्णा तिवारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मारपीट करने वाला दिव्यांशु पटेल नाम का अफसर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) था। इस घटना की चौतरफा निंदा हुई और 12 जुलाई को संपादकों की सर्वोच्च संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक औपचारिक निंदा बयान जारी करते हुए अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर दी। तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अधिकारी द्वारा पीड़ित पत्रकार को घर में बुलाकर लड्डू खिलाकर मामला निपटाया जा चुका

था। पत्रकार भी वीडियो में संतुष्ट दिख रहा था। अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि गिल्ड ने मांग की थी।

ऐसे मामलों से स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता के द्वंद्व को भी समझा जाना चाहिए। आखिर पीड़ित पत्रकार के पास अधिकारी से सुलह करने के अलावा और क्या रास्ता बचता है? उसे वहीं पर रह कर खाना कमाना है और काम भी है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रकरण उठ जाने पर भी उसकी कार्यस्थितियों में कोई बदलाव आ जाए, इसकी गुंजाइश कम होती है। हां, इस मामले में एडिटर्स गिल्ड से जरूर एक संकेत लिया जाना चाहिए कि नयी कार्यकारिणी आने के बाद संस्था ने लगातार उत्तर प्रदेश पर केंद्रित बयान जारी किये हैं, बगैर मुंह देखे कि पीड़ित पत्रकार का कद और रसूख क्या है। नेशन लाइव टीवी की गिरफ्तारियों से लेकर सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर संदिग्ध पुलिस जांच और रमन कश्यप की हत्या तक तकरीबन हरेक मामले में गिल्ड ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया और मुख्यमंत्री के नाम पत्रकार सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा, वह अपने आप में उत्तर प्रदेश में प्रेस की आजादी पर एक गंभीर टिप्पणी है (देखें अनुलग्नक)।

न सिर्फ एडिटर्स गिल्ड बल्कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर सीपीजे, आरएसएफ और प्रादेशिक पत्रकार संगठनों की चिंताओं के केंद्र में उत्तर प्रदेश की घटनाओं का होना बताता है कि चारों ओर से पत्रकारों की यहां घेराबंदी की जा रही है। नये आइटी कानून के माध्यम से डिजिटल पत्रकारों के पर कतरने के बाद इस कड़ी में ताजा उदाहरण 8 फरवरी 2022 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक 'केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश' है। यह दिशानिर्देश मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर केंद्रित है जिसमें कहा गया है कि देश की "सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता" के साथ-साथ "सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता" के लिए प्रतिकूल तरीके से काम करने वाले पत्रकार अपनी सरकारी मान्यता खो देंगे। इस किस्म के आदेश की आहट कुछ महीने पहले ही सुनायी पड़ गयी थी जब पत्रकारों को संसद का सत्र कवर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

बीते पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश का पत्रकारिता परिदृश्य जिस तरह विकसित हुआ है, कहा जा सकता है कि पेगासस के संदर्भ में अभिव्यक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की 'ऑरवेलियन' चिंताएं यहां एक नहीं बारम्बार चरितार्थ हो चुकी हैं और हर आये दिन एक नये आयाम में सामने आ रही हैं। महामारी के बहाने निर्मित किये गये एक भयाक्रान्त वातावरण के भीतर मुकदमों, नोटिसों, धमकियों के रास्ते खबरनवीसी के पेशेवर काम को सरकार चलाने के संवैधानिक काम के खिलाफ जिस तरह खड़ा किया गया है, पत्रकारों की घेरेबंदी अब पूरी होती जान पड़ती है।

अनुलग्नक

लखीमपुर खीरी रमन कश्यप हत्याकांड पर PUCL की संक्षिप्त रिपोर्ट

प्रेस नोट
तिकुनिया लखीमपुर खीरी नरसंहार

देश भर में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए समर्पित संगठनों के एक समूह द्वारा तैयार की गई एक तथ्यान्वेषण रिपोर्ट।

दिसंबर 2021

तिकुनिया में 3 अक्टूबर, 2021, को शाँतमई ढंग से विरोध-प्रदर्शन कर रहे चार किसानों, एक पत्रकार और भाजपा से सम्बन्धित तीन और लोगों की हुई मौतों की जाँच करने के लिए 11 सदस्यीय 'अखिल भारतीय निश्पक्ष तथ्यान्वेषी दल' का गठन किया गया था। कुछ दिनों बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और कुछ उल्लेखनीय गिरफ्तारियाँ भी हुईं। तथ्यान्वेषी दल ने 27 से 29 अक्टूबर तक इलाके का दौरा किया था। तथ्यान्वेषी दल ने नरसंहार स्थल पर जाकर स्थानीय लोगों के साथ बैठकें की, घटना में मारे गए किसानों के पारिवारिक सदस्यों, वकीलों, सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन अपने बयान कलमबद्ध करवाने वालों समेत चश्मदीद गवाहों से भेंट की और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध दस्तावेजों और विडीयो की जाँच की।

तथ्यान्वेषी दल ने सम्बन्धित मंत्री और विधान-सभा चुनाव की उमीदवारी के लिए हाथ-पैर मार रहे उसके बेटे द्वारा खेली जा रही साम्प्रदायिक राजनीति को नोट किया, और इन बाप-बेटे की जोड़ी द्वारा किसान आन्दोलन का अपराधीकरण करने, डराने-धमकाने और आन्दोलन को बदनाम करने की कोशिशों और शाँतमई ढंग से विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ साजिशें रचने और खुद के लिए कानून का कोई भय न होने वाला माहौल बनाने का भी तथ्यान्वेषी दल द्वारा नोटिस लिया गया।

तथ्यान्वेषी दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यह गृह-राज्य मंत्री के बेटे की अगुवाई में पुलिस के सहयोग से किया गया एक पूर्व नियोजित हमला था। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है:-

- जब किसानों का शाँतिपूर्ण ढंग से विरोध-प्रदर्शन समाप्त हो रहा था और किसान अपनी रैली समाप्त करके लौट रहे थे, अजय मिश्रा टैनी के परिवार से सम्बन्धित तीन तेज रफ्तार एसयूवी कारों को उस संकरी सड़क पर देखा गया, जिससे किसान जा रहे थे। और इन कारों ने किसानों को पीछे से टक्कर मारी और उन्हें कुचल दिया। किसान नेता तेन्जिदर सिँह विर्क के नेतृत्व वाले किसानों के समूह को इन कारों ने निशाना बनाया। हमले में चार किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई और विर्क सहित कई अन्य किसान गम्भीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इस हिंसक हमले का नेतृत्व करने के लिए टैनी के बेटे आशीष मिश्रा ऊर्फ मोनू को दोषी ठहराया और कहा कि आशीष और उसके लोगों ने जानबूझकर किसानों पर एसयूवी चढ़ाई। कई किसानों ने इस नरसंहार को अपनी आँखों से देखा और अपने मोबाइल फोन कैमरों के माध्यम से घटना के वीडियो रिकॉर्ड किए।

- इतफाकन विपरीत दिशा से उसी समय एक बस सामने आ गई। नतीजतन, पहली दो तेज-रफ्तार कारें सड़क के किनारे फिसल गईं। एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर। तीसरी कार बहुत धीमी गति से बस के पास से गुजर गई। किसानों ने इस कार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यदि इतफाक से बस नहीं आई होती तो हमलावर टक्कर मारकर भागने की अपनी सोची समझी साजिश में सफल हो जाते।
- एक अहम गतिविधि के तौर पर घटना की जाँच कर रहे विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने 14 दिसंबर, 2021 को सत्र न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि लखीमपुर-खीरी में हुई हिंसा किसी लापरवाही का परिणाम नहीं थी बल्कि इसे प्रदर्शनकारियों को मारने की पूर्व नियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी के प्रावधानों में संशोधन करने का विचार भी विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने सत्र न्यायालय के समक्ष रखा। एसआईटी ने लिखा है कि आईपीसी की धारा 307 (जानबूझकर हत्या), 326 (खतरनाक हथियार से जख्मी करना), 34 (एक संयुक्त साजिश को अंजाम देने के लिए कई लोगों द्वारा की गई कार्रवाई) और आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 को एफआईआर में शामिल किया जाए और लापरवाह ड्राइविंग, गैरकानूनी इकट्ठ, आपराधिक साजिश और दूसरी धाराएँ वापस ली जाएँ।
- भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की मौत पर तथ्यान्वेषी समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इस बात के सबूत मिलते हैं कि ये कार्यकर्ता घायल हुए थे और उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि अमर उजाला अखबार में 17 अक्टूबर, 2021 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद अजय मिश्रा टैनी ने स्वीकार किया था कि घायल श्याम सुंदर निषाद पुलिस हिरासत में था और उसे एंबुलेंस से उतार कर मारा गया। यह एक बहुत ही गम्भीर आरोप है जिसकी गहनता से जाँच होनी चाहिए। इसी तरह मिश्रा के चालक ओम प्रकाश की मौत की भी गहन जाँच होनी चाहिए क्योंकि चालक की मौत से मामले के मुख्य आरोपी को फायदा होगा। तथ्यान्वेषी दल को टक्कर के बाद तत्काल प्रतिक्रिया के अलावा किसानों द्वारा हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला। घायलों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। भाजपा के तीनों कार्यकर्ताओं की मौत की गहन जाँच होनी चाहिए।
- अपने अहुदे के प्रभाव के कारण पुलिस बल पर गृह-राज्य मंत्री अजय मिश्रा के मजबूत नियंत्रण और व्यक्तिगत लाभ के लिए पुलिस बल और अदालतों का उपयोग करने और हिंसा के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, तथ्यान्वेषी समिति का दृढ़ विश्वास है कि एक मंत्री के पद पर बने रहने के कारण इस मामले में हेराफेरी हो सकती है और न्याय प्रशासन कमजोर हो सकता है।

तथ्यान्वेषी समिति विशेष तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि-

(1) तीन अक्टूबर की घटना को पूरी तरह से तभी समझा और जाँचा जा सकता है जब घटनाक्रम को सितंबर 2021 से जोड़ा जाए और जाँच का सम्बन्ध भूमि सम्बन्धों के सन्दर्भ और साम्प्रदायिक आधार पर लोगों में विभाजन की संगठित कोशिशों को प्राथमिकता से शामिल किया जाए।

(2) इस सारे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका बेहद निंदनीय है। पुलिस ने हमलावरों का साथ दिया। हमलावरों को मौके पर घुसने और फिर भागने में मदद की। और पुलिस लगातार झूठ बोलती पाई गई।

(3) पुलिस को उन भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत के बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिन्हें नरसंहार स्थल पर पुलिस को सौंप दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनमें से एक, भाजपा कार्यकर्ता श्याम सुंदर निषाद भी पुलिस हिरासत में जीवित था और चश्मदीद गवाहों के अनुसार पैदल ही एम्बुलेंस तक

पहुँचा था। बाद में वह मृत पाया गया। पुलिस उसकी मौत की व्याख्या कैसे करती है? निष्पक्ष जाँच से ही सच्चाई का पता चल सकता है।

(4) इस तथ्यान्वेषी समिति ने किसानों के शाँतिपूर्ण एलैग मार्च से पहले, विरोध के दौरान और इस जघन्य घटना के बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा बोले गए कई झूठ और गलत सूचनाओं का पर्दाफाश किया।

(5) पीड़ितों के परिवार के सदस्यों की गवाही से यह बात भी सपष्ट हुई कि राज्य के जीर्ण-शीर्ण बुनियादी ढाँचे और घटिया स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भी मनुष्य के कीमती जीवन का नुक्सान हुआ। यदि उस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होती तो कम से कम तीन और जिन्दगियाँ बचाई जा सकती थी। ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है और इस सम्बन्ध में अजय कुमार मिश्रा टैनी एक असफल नेता साबित हुआ है।

(6) पीड़ितों के परिवारों और अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे इलाके में पूरी तरह भय का माहौल बना हुआ है।

(7) आईपीसी की धारा 144 का मनमाने ढंग से इस्तेमाल, लोगों की आवाजाही पर रोक, किसान नेताओं, प्रेस और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के पीड़ितों के परिवारों से मिलने पर रोक, ये सब आरोपी के पक्ष में जाता है। इस प्रथा को कानूनी रूप से चुनौती देने की जरूरत है और लोगों के आने-जाने और इकट्ठा होने पर मनमानी रोक लगाया जाना बंद होना चाहिए।

(8) भीड़ नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल (नियम) की माँग है कि पुलिस बल के पास घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने और उन्हें आगे के चिकित्सा उपचार के लिए तुरंत एक अच्छे अस्पताल में पहुँचाने के लिए परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में भी पुलिस बुरी तरह विफल रही है।

(9) घटना से एक दिन पहले प्रशासन को सूचना मिल चुकी थी कि उपमुख्यमंत्री ने बनवीरपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तिकुनिया हेलीपैड पर उतरने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इस जानकारी को किसानों से छुपाकर इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा किया।

(10) जिस तरह से किसानों को 500 मीटर से कम के दायरे से आगे न जाने के लिए बेरिकेडिंग और बातचीत के जरिए राजी किया गया, उससे वे उस दायरे से गुजर रहे तेज रफ्तार वाहनों का आसान शिकार बन गए और वाहनों के नीचे कुचल दिए गए। यह सब जिस सटीकता के साथ हुआ, उससे पता चलता है कि यह घटना पूर्व नियोजित थी।

निम्नलिखित कारण इस निष्कर्ष का आधार बनते हैं:- (क) इस रिपोर्ट में उल्लिखित घटना की पृष्ठभूमि। (ख) घटनाओं का कालक्रम, (ग) नरसंहार के बाद की घटनाओं का कालक्रम।

रिपोर्ट में घटना की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम के मुख्य पहलुओं को इस प्रकार दर्ज किया गया है:- अजय कुमार मिश्रा टैनी द्वारा घटना से कुछ दिन पहले किसानों को डराने-धमकाने के लिए जो भाषण दिया था, उससे किसान बहुत गुस्से में थे। उस भाषण में टैनी ने किसानों से कहा था, ''सुधार जाओ, नहीं तो हम खुद आपको सुधार देंगे। बस दो मिनट लगेंगे।'' तीन अक्टूबर को किसानों ने शाँतिपूर्वक तिनुकिया में हेलीपैड पर कब्जा कर लिया, जिस पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरना था। किसानों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपमुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले ही बदल चुका है और वह अब हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा। राज्य प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धारा 144 लागू करके और प्रेस, राजनीतिक प्रतिनिधियों और किसान नेताओं को तिनुकिया में प्रवेश करने से रोककर पूरे जिले को एक किले

में बदल दिया गया। जिले से कोई जानकारी बाहर न जा सके, इसलिए इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था, जिसे 8 अक्टूबर को फिर से शुरू किया गया। किसान नेता और स्थानीय पत्रकार हत्याकांड की खबर तत्काल जिले के बाहर के लोगों तक नहीं पहुंचा सके। इसी नाजुक समय का उपयोग अजय मिश्रा टैनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा ने नरसंहार का एक सार्वजनिक वृतान्त निर्मित करने के लिए किया, जिसमें किसानों को हिंसा और मौतों के लिए दोषी ठहराया था।

- शाम और रात को कई टीवी चैनलों के साथ एक साक्षात्कार में, पिता-पुत्र की जोड़ी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जोरदार खंडन किया और जोर देकर कहा कि वे हिंसा स्थल पर मौजूद नहीं थे। अजय मिश्रा ने किसानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और एक एसयूवी चालक को मारने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी किसानों ने कारों के काफिले पर पथराव किया जिससे कारों का नियंत्रण खो गया और दुर्घटना हो गई। गोदी मीडिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं का भीड़ द्वारा मारे जाने की कहानी को रिपोर्ट किया और पिता-पुत्र की कहानी के पक्ष में जनमत जुटाने में मदद की। और इस बात को दबाने की कोशिश की कि वे सीधे तौर पर नरसंहार में शामिल थे।

फैक्ट फाइंडिंग टीम का निष्कर्ष और माँग

1. अजय मिश्रा टैनी का अतीत और वर्तमान शासन में उसे मिली अथाह ताकत, जाँच को प्रभावित करने, तथ्यों को अपने पक्ष में तोड़ने-मरोड़ने, उसकी और उनकी पार्टी के लाभ के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया करवाती है।
2. इसलिए, एक निष्पक्ष जाँच के लिए, अजय मिश्रा को उसके मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए और उसके खिलाफ 120 सीआरपीसी की शिकायत पर कारवाई की जानी चाहिए।
3. पुलिस की भूमिका निंदनीय पाई गई। पुलिस ने अपराधियों का साथ दिया, उसके प्रवेश और अपराध को अंजाम देने के बाद वहाँ से भागने, उसके झूठ, उसके कवर अप में मदद की गई है।
4. राज्य की दण्ड-मुक्ति को एक उचित प्रक्रिया के माधयम से चुनौती दी जानी चाहिए, जिसके लिए महतवपूर्ण है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच हो। ऐसा करने के लिए अजय मिश्रा को उसके पद से हटाया जाना चाहिए।
5. पारिवारिक साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि जीर्ण-शीर्ण राज्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमत पर ढेरों जाने चली गई। यदि क्षेत्र में उचित अस्पताल सुविधाएँ उपलब्ध होतीं, तो कम से कम कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि की होती है, लेकिन अजय मिश्रा टैनी अपनी भूमिका निभाने में बुरी तरह किल रहा।
6. इलाके में दहशत का माहौल है। राज्य को सभी गवाहों की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और उन्हें बिना किसी डर के गवाही देने की अनुमति देनी चाहिए।
7. इंटरनेट बंद करने की प्रथा, जिसका वर्तमान शासन धड़ले से इस्तेमाल कर रहा है, को समाप्त किया जाना चाहिए। यह पीड़ितों को खामोश करने का काम करता है और अपराधियों को सार्वजनिक रूप से अपने अनुकूल अपना आख्यान निर्मित करने की अनुमति देता है। इस प्रथा को चुनौती दी जानी चाहिए।
8. धारा 144 का मनमाने ढंग से इस्तेमाल और अपराधियों के लाभ के लिए लोगों, प्रेस और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपराध स्थल पर पहुँचने से रोके जाने को चुनौती दी जानी चाहिए।

9. भीड़नियंत्रण प्रोटोकॉल में कहा गया है कि पुलिस प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए ले जाने के कुशल तरीके का प्रबंध करे। पुलिस समय पर इलाज उपलब्ध कराने में किल रही।
10. घटना के एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम के बनवीरपुर में होने वाले कार्यक्रम के रद्द होने की जानकारी थी। इसे किसानों से दूर रखकर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इलाके में तनाव पैदा करने में अपना योगदान दिया।
11. किसानों द्वारा सौंपे गए भाजपा कार्यकर्ताओं में से एक श्याम सुंदर निषाद, पुलिस के पास जीवित था और एक एम्बुलेंस तक पहुँच गया था। बाद में उसे मृत पाया गया। पुलिस उसकी मौत की व्याख्या कैसे करती है? अजय मिश्रा टैनी ने सार्वजनिक रूप से गवाही दी कि श्याम सुंदर निषाद एम्बुलेंस से उतारकर पुलिस हिरासत में मारा गया, यह गहन जाँच की माँग करता है।
12. यहाँ तक कि टैनी के ड्राइवर ओम प्रकाश की मौत की भी गहन जाँच की माँग की जाती है, क्योंकि उसकी मौत से आशीष मिश्रा को फायदा हुआ है।
13. निर्दोष किसानों, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें रिहा किया जाए।

टीम के सदस्य

- प्रो. जगमोहन सिँह, महासचिव, जमहूरी अधिकार सभा (पंजाब) 98140-01836
- नरभिंदर सिँह, जमहूरी अधिकार सभा (पंजाब)
- प्रितपाल सिँह, जमहूरी अधिकार सभा (पंजाब)
- एडवोकेट एन.के. जीत, जमहूरी अधिकार सभा (पंजाब)
- सीमा आजाद, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल)
- गोपाल सुन्दरराजन, दी कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईटस (सीपीआरडी) तामिलनाडु
- मनु अकावूर, दी कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईटस (सीपीआरडी) तामिलनाडु
- डॉ. सुखदेव हुन्दल, जमहूरी अधिकार सभा (हरियाणा)
- मोहम्मद फैजल, क्रान्तिकारी लोक अधिकार संगठन (उत्तर प्रदेश)
- कमलेश, परिवर्तनगामी छात्र संगठन (उत्तर प्रदेश)
- नवशरण सिँह, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश केंद्रित बयान और पत्र

EGi
Editors Guild of India

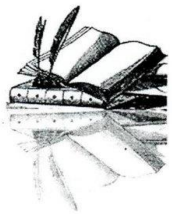

PRESS STATEMENT

October 5th, 2021

The Editors Guild of India is shocked by the death of Raman Kashyap, a TV journalist who was reporting on Lakhimpur Kheri's farmers protest on October 3. Kashyap was killed along with eight others, in the violence that erupted after some vehicles were driven through the protesting farmers, allegedly under the instructions of Ashish Mishra, son of union minister of state, Ajay Kumar Mishra.

There are competing versions about Kashyap's death including a version that claims he died of bullet wounds. What is clear is that Kashyap was reporting on the events of the day when the horrific incident of the convoy running through protesting farmers happened, killing some of them. An independent inquiry is therefore needed to establish the cause of Kashyap's death.

In what is clearly a terror attack meant to spread fear amongst the farmers, the killing of Kashyap raises many questions. The Editors Guild demands that the death of Kashyap be separately probed by a Court led special investigation team to ascertain the circumstances of his death and also attempt to recover and use the footage of his camera to build the sequence of events leading to his death.

EGI is concerned about the varying versions of the incident in different sections of the media. It is imperative for the media to report the facts and not versions.

Seema Mustafa / Sanjay Kapoor / Anant Nath (signatures)

Seema Mustafa
President

Sanjay Kapoor
General Secretary

Anant Nath
Treasurer

Address: 4/7- A, INS Building, Rafi Marg, New Delhi-110001

EGi
Editors Guild of India

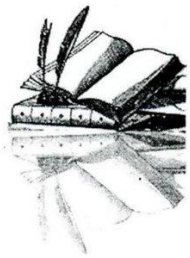

PRESS STATEMENT

July 23rd, 2021

The Editors Guild of India is concerned about the Income Tax raids on July 22, at the offices of country's leading newspaper group, Dainik Bhaskar, as well as a Lucknow based independent news channel, Bharat Samachar. They come against the backdrop of in depth reporting on the pandemic by Dainik Bhaskar, which brought to fore the gross mismanagement by government authorities and the immense loss of human lives. In a recent webinar hosted by the Guild, Om Gaur, the National Editor of Bhaskar had stated that their advertising from government departments had been cut after the recent critical coverage of state authorities. He had also written an op-ed in the New York Times, headlined 'The Ganges Is Returning the Dead. It Does Not Lie.'

Bharat Samachar, too, has been subjected to raids by the tax authorities. It is one of the few channels in UP that has been asking difficult questions from the state government with respect to pandemic management.

Notwithstanding the merits of the case, the timing of these raids is concerning given the recent critical coverage by both the organisations.

In February 2021, the Enforcement Department had conducted raids at the office of NewsClick.in, which had been at the frontline of reporting on the farmers agitation and the anti-CAA protests.

EGI is therefore concerned that government agencies are being used as a coercive tool to suppress free and independent journalism. This is all the more disturbing given the recent media reports on the wide spread surveillance of journalists and civil society activists using the Pegasus software.

Seema Mustafa
President

Sanjay Kapoor
General Secretary

Anant Nath
Treasurer

Address: 4/7- A, INS Building, Rafi Marg, New Delhi-110001

EGi
Editors Guild of India

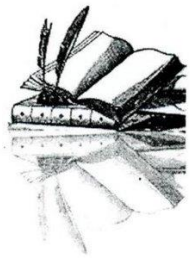

13 जुलाई, 2021

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में पत्रकारों और मीडिया के प्रति राज्य के अधिकारियों द्वारा लगातार सख्त प्रवृत्ति से बहुत उद्विग्न है। ताजा घटना 10 जुलाई, 2021 को यूपी के उन्नाव जिले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) द्वारा एक पत्रकार पर हमला करने की है, जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान कवर कर रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, एक स्थानीय पत्रकार कृष्णा तिवारी को दिव्यांशु पटेल (सीडीओ) और कथित तौर पर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा जाता है।

ईजीआई इस घटना को बेहद निंदनीय और कार्रवाई योग्य मानता है। यह घटना यूपी राज्य में पत्रकारों के बढ़ते उत्पीड़न की पृष्ठभूमि के खिलाफ आई है, क्योंकि प्रशासन ने पत्रकारों को अपराधों, राज्य की ज्यादतियों और महामारी के प्रबंधन पर स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने से डराने के प्रयास में दंडित, दंडित और कैद किया है। . अक्टूबर 2020 में हाथरस में एक दलित महिला के बलात्कार और हत्या की रिपोर्ट करने के दौरान गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, अभी भी कठोर यूएपीए के तहत जेल में हैं | उनके परिवार और नागरिक समाज द्वारा निष्पक्ष परीक्षण और उपचार वहन करने की कई अपीलों के बावजूद भी।

भले ही सीडीओ ने बाद में पत्रकार से माफी मांग ली हो, लेकिन प्रशासन द्वारा भारी सख्ती का यह रवैया मीडिया के लोकतांत्रिक अधिकारों को ठेस पहुंचा रहा है, जो राज्य में अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

ईजीआई की मांग है कि अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और राज्य में स्वतंत्र पत्रकारिता के माहौल में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

Seema Mustafa **President**	**Sanjay Kapoor** **General Secretary**	**Anant Nath** **Treasurer**

Address: 4/7- A, INS Building, Rafi Marg, New Delhi-110001

EGi
Editors Guild of India

PRESS STATEMENT

June 17th, 2021

The Editors Guild of India condemns the filing of First Information Reports (FIRs) by the Uttar Pradesh Police against The Wire and several other journalists, for their tweets on an assault on an elderly Muslim man in Ghaziabad on June 5th. In the video that was posted by those charged, the man is seen alleging that he was beaten up by some people and was forced him to chant ' Jai Shree Ram'.

Several media organizations and journalists, besides the ones charged by the police, posted this video on their social media feeds. Subsequently there was an alternate version offered by the UP Police claiming that the assault was borne out of a dispute regarding a talisman that the elderly man had sold to some people, which was also reported by these media organizations and journalists.

The Guild is deeply concerned by the UP Police's track record of filing FIRs against journalists to deter them from reporting serious incidents without fear of reprisals. It is the duty of the journalists to report on the basis of sources and in case facts become contested later on, to report the emerging versions and facets. For police to wade into such professional calls by journalists and attribute criminality to their actions is destructive of freedom of speech, which is constitutionally protected and is an entrenched feature of the rule of law.

Further, it is quite evident that the police has been discriminatory in targeting those media organizations and journalists- when thousands had tweeted the video- that have been critical of the government and it's policies. The Guild condemns this wanton misuse of laws to criminalize reporting and dissent to harass independent media and demands that the FIRs be withdrawn immediately.

Seema Mustafa	**Sanjay Kapoor**	**Anant Nath**
President	**General Secretary**	**Treasurer**

Address: 4/7- A, INS Building, Rafi Marg, New Delhi-110001

EGi
Editors Guild of India

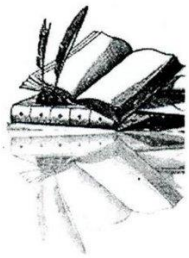

PRESS STATEMENT

June 14th, 2021

The Editors Guild of India is shocked by the cavalier manner in which Uttar Pradesh Police is treating the mysterious death of TV journalist, Sulabh Srivastava, in Pratapgarh. Srivastava, who had been threatened by the liquor mafia for exposing their wrongdoings, had recently written a letter to the police expressing grave apprehensions for his life. He believed that some people were following him. The authorities paid no heed to his fears. Srivastava died a couple of days after he wrote the letter to the police. The police is passing off his death as being caused by an accident, claiming that his bike rammed into a handpump.

His death comes at a time when media is facing increasing pressures from central and state governments who insist that they follow the official narrative regarding the administration's handling of the pandemic. What is further worrying is that the police and the local authorities liberally and unjustifiably use laws such as sedition and UAPA to file charges and arrest journalists. This is against the spirit of the judgment given by the Supreme Court in Kedar Nath Singh case and re-iterated in the recent sedition case against Vinod Dua.

Journalists and cartoonists critical of the government are also being targeted on social media, as pressures are being mounted by the government on these platforms to remove such critical journalists on the specious ground that they are violating the law of the land. All of this is contrary to the commitments that Prime Minister Narendra Modi made at the G-7 summit to democracy, openness and against authoritarianism.

Seema Mustafa Sanjay Kapoor Anant Nath

Seema Mustafa
President

Sanjay Kapoor
General Secretary

Anant Nath
Treasurer

Address: 4/7- A, INS Building, Rafi Marg, New Delhi-110001

EGi
Editors Guild of India

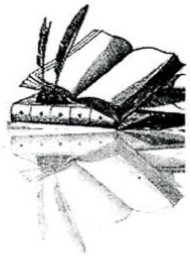

PRESS STATEMENT

April 26, 2021

The Editors Guild of India is deeply disturbed by reports of inhuman treatment being meted out to the journalist Siddique Kappan, who has been in custody since October 2020, under the draconian UAPA, for trying to report on the rape and death of a Dalit girl in Hathras, Uttar Pradesh. His wife has alleged that her husband has been tied to a bed and is neither able to take food nor access toilet, while undergoing treatment at a Mathura Hospital for Covid-19. This is shocking and should stir the conscience of the nation that a journalist is being treated in this cruel manner and being denied basic rights. The Uttar Pradesh Chief Minister, Ajay Mohan Bisht, (Yogi Adityanath), has been ignoring the demands from his family and the civil society for fair treatment of the journalist. It is further shocking that the Supreme Court of India has yet not intervened in this case to ensure a fair trial of the journalist, even though the Habeas Corpus petition challenging his arrest has been pending before the court for the past six months. All of this goes against the basic canons of a constitutional democracy where independent journalistic enterprises need to be protected rather than repressed.

The Editors Guild of India had written a letter to the Chief Minister of UP in November 2020, highlighting several instances of state persecution and violence against journalists, including that of Kappan. Since then, the situation has only worsened. Recently, the CM threatened to seize the property of anyone who reported on the paucity of oxygen in hospitals in the state. Such declamations have a chilling effect on media freedom, at a time when there is urgent need for objective reporting and accountability on the worsening pandemic.

EGI demands that Siddique Kappan be given proper medical treatment at the earliest and that he be treated with dignity. The Guild also urges the Supreme Court to urgently take up the pending writ petition and give him a fair trial.

Seema Mustafa
President

Sanjay Kapoor
General Secretary

Anant Nath
Treasurer

Address: 4/7- A, INS Building, Rafi Marg, New Delhi-110001

EGi
Editors Guild of India

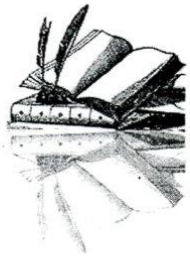

09 नवम्बर 2020

श्री योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री सचिवालय
लोक भवन, विधानसभा मार्ग
लखनऊ-226001
उत्तर प्रदेश

विषय-उत्तर प्रदेश में संवादमाध्यमों की स्वतंत्रता एवं पत्रकारों के अधिकार

मान्यवर,

उत्तर प्रदेश में प्रेस की स्वतंत्रता और श्रमजीवी पत्रकारों के अधिकार और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में आग्रह करने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनके फलस्वरूप उ प्र में मुक्त, निर्भय और स्वाधीन पत्रकारिता के संबंध में गहरी चिंता हुई।

मुंबई में एक टीवी चैनल के संपादक की गिरफ्तारी पर प्रेस की स्वतंत्रमा के अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए आपने उचित ही ध्यान दिलाया। उत्तर प्रदेश में प्राधिकारियों द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों को धमकाने, प्रताड़ित करने के कुछ गंभीर मामलों की तरफ ध्यान जाता है जिनमें पत्रकारों को कर्तव्य पालन करने से रोका गया। कई पत्रकारों को अनुचित तरीके से फर्जी आरोपों में बंदी बनाया गया। इस तरह के कुछ प्रकरण आपकी जानकारी के लिए-

1. सिद्दीक कप्पन-दिल्ली निवासी पत्रकार, मलयालम न्यूज पोर्टल अजीमुखम के लिए काम करते हैं। तीन अन्य सहयोगियों के साथ दलित कन्या के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के लिए हाथरस जाते समय पांच अक्टूबर 2020 को कप्पन को मथुरा में पकड़ा गया। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून अधिनियम के अनुभग-17 के अंतर्गत उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। उनके दो साथी, जो केरल के पापुलर फ्रंट आफ इंडिया की विद्यार्थी शाखा से संबंधित बताए जाते हैं, और कप्पन को मथुरा जेल भेजा गया। पुलिस का दावा है कि वे हाथरस बलात्कार कांड के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने के लिए साजिश में शामिल हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। मथुरा के न्यायायिक दंडाधिकारी ने 4 नवम्बर को उ प्र स्पेशल टास्क फोर्स को पूछताछ के लिए 48 घंटे का पुलिस रिमांड मंजूर किया। कप्पन अभी भी जेल में बंद हैं। उनके परिवारजनों को कप्पन से बात तक करने की अनुमति नहीं दी गई।
2. सुप्रिया शर्मा-स्क्रोल की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा के विरुद्ध 18 जून 2020 को अनुसूचित जाति जनजाति कानून एवं भारतीय दंड विधान की धारा-501 (ऐसी सामग्री छापना या उकेरना जिससे मानहानि होती हो) तथा 269 (विधिविरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करना, जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है) के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया। सुप्रिया ने प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में दुर्व्यवस्था से संबंधित धारावाहिक समाचार कथाएं लिखीं थीं। प्रधानमंत्री ने चुनाव क्षेत्र के डोमरी गांव को दत्तक लिया। इस गांव की निवासी माला देवी के नाम से पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत का सार यह था कि सुप्रिया ने गलत लिखा कि कोरोना महामारी के कारण लाकडाउन के दौरान आहार नहीं मिलने के कारण माला देवी की तबियत बिगड़ी।

EGi
Editors Guild of India

3. बिजनौर के पांच पत्रकार- आशीष तोमर, शकील अहमद, लाखन सिंह, आमिर खान, एवं मोइन अहमद- के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के 153 ए (धर्म, भाषा, नस्ल, निवास वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करना), दफा-268 सार्वजनिक स्थान पर अशांति फैलाना एवं 503 आपराधिक धमकी व सूचना-प्रौद्योगिकी अधिनयम के 66 ए के अंतर्गत 7 सितम्बर 2020 को मामला दर्ज किया गया। प्राथिमकी के अनुसार तोमर और अहमद ने मंडवार पुलिस थाने के अंतर्गत तितरवाला बसी गांव के वाल्मीकि परिवार के बारे में बेबुनियाद खबर प्रसारित की। खबर का सार यह था कि स्थानीय बाहुबलियों ने गांव के हैंड पंप से पानी भरने से धमकाकर रोक दिया था इसलिए वाल्मीकि परिवार ने घर बेचने का फैसला किया। पत्रकारों ने कहा कि उनकी खबर सही है। पत्रकारों की संघर्ष समिति के तीव्र विरोध के बाद जिला प्रशासन को मामला वापस लेना पड़ा।
4. रवीन्द्र सक्सेना- टुडे-24 समाचार चैनल के रिपोटर रवीन्द्र सक्सेना के विरुद्ध अनुसूचित जात-जनजाति कानून तथा आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने सीतापुर जिले के माहोली तहसील में क्वारेंटाइन सेंटर में कुप्रबंधन के समाचार से कुपित प्रशासन ने रवीन्द्र को गिरफ्तार का इरादा छोड़ दिया क्यों कि पत्रकारों ने जोरदार विरोध किया। हालां कि उनके विरुद्ध दर्ज प्रा ामकी वापस नहीं ली गई।
5. विजय विनीत और मनीष मिश्र- जनादेश नाम के दैनिक समाचार पत्र में कार्यरत पत्रकारों की 26 मार्च 2020 को खबर छपी जिसमें वाराणसी जिले के कोइरीपुर गांव के मुशहर समुदाय की तकलीफों का विवरण था। बच्चों को घास-पत्ती खाते हुए दिखाया गया था। दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।
6. असद रिज़वी- लखनऊ में स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। हाथरस में दलित कन्या के साथ सामूहिक बलात्कार के विरोध में 2 अक्टूबर को प्रदर्शन हुए। समाचार संकलन करते समय रिज़वी के साथ मारपीट की गई। रिज़वी ने पुलिस तथा राज्य प्रशासन को लिखित शिकायत कर बताया है कि उन्होंने बार बार बताया कि मैं पत्रकार हूं और समाचार संकलन कर रहा हूं। इसके बावजूद सात-आठ पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने मोबाइल तोड़ने की कोशिश की तथा मेमोरी कार्ड जब्त कर लिया।

आप देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस नाते आप संवैधानिक अधिकारो की रक्षा की राज्य की परंपरा से भली-भांति परिचित हैं। पूरी दुनिया इन दिनों महामारी की पीड़ा से ग्रसित है। ऐसे में पत्रकारों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने तथा बचाव के लिए संवाद माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हमारा आग्रह है कि आप जेल में बंद पत्रकारों को रिहा करें, उनके विरुद्ध दर्ज मामले वापस लें, तथा राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

एडिटर्स गिल्ड की इच्छा है कि राष्ट्रीय संपादकों का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचकर आपसे मुलाकात करे तथा प्रशासन से मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करने में सहयोग करे जिससे पत्रकार मुक्त वातावरण में निर्भय होकर काम कर सकें।

सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा में-

सधन्यवाद-

Seema Mustafa
सीमा मुस्तफा
अध्यक्ष

Sanjay Kapoor
संजय कपूर
महासचिव

Anant Nath
अनंत नाथ
कोषाध्यक्ष

Address: 4/7- A, INS Building, Rafi Marg, New Delhi-110001

EGi
Editors Guild of India

June 19, 2020

The Editors Guild of India is deeply concerned over the registration of a First Information Report (FIR) at Varanasi's Ramnagar police station against Scroll Executive Editor Supriya Sharma and its Chief Editor over a report published from Varanasi's Domari village. The FIR was filed on June 13 under Sections 269 (negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life) and 501 (printing or engraving matter known to be defamatory) of the Indian Penal Code (IPC) as also under the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act (SC/ST Act). This followed a complaint by Mala Devi, who was quoted by Supriya Sharma in her report, published on Scroll.in on June 8.

The Guild has also noted the reported statement from Scroll.in saying that it stood by the article in question. The statement also clarified that it had interviewed Mala Devi in Domari village, Varanasi, Uttar Pradesh, on June 5, 2020 and that her statements had been reported accurately in the article titled, "In Varanasi village adopted by Prime Minister Modi, people went hungry during the lockdown."

In view of the categorical statement from Scroll.in, the Guild is of the view that the use of the various Sections of the IPC and the SC/ST Act are an overreaction and will seriously undermine freedom of the media. The use of criminal provisions of the law against journalists has now become an unhealthy and despicable trend that has no place in any vibrant democracy. It needs to be resisted as well as eliminated. The Guild respects all laws of the land as also the right of Mala Devi to defend herself against any acts of injustice. But it also finds the flagrant misuse of such laws unjustifiable and reprehensible. Worse, the increasing frequency of such misuse of laws by the authorities is tantamount to shooting the messenger and destroying a key pillar of India's democracy.

Shekhar Gupta
President

AK Bhattacharya
General Secretary

Sheela Bhatt
Treasurer

EGi
Editors Guild of India

September 02, 2019

The Editors Guild of India condemns the Uttar Pradesh government's action of filing an FIR under serious sections of criminal law against journalist Pawan Jaiswal for his report that mere rotis and salt were being served to school children as their lawfully guaranteed mid-day meal in Siyur primary school, Mirzapur.

It is a cruel and classic case of shooting the messenger. It is precisely exposés such as these that show how valuable free and fearless journalists are to a democratic society. It is shocking that instead of taking action to fix what is wrong on the ground, the government has filed criminal cases against the journalist. Even if the government believes that his report is wrong, there are easy and conventional redresses available. Using the IPC and police is no way to respond to this.

The Guild urges that the state government withdraw these cases forthwith and ensure that the journalist is not put to any further harm or harassment.

The Guild also expresses grave concern over recent incidents of restrictions on the overseas travel of journalists. The latest being the denial of travel permission at the airport for journalist Gowhar Geelani, who works for a German media organisation. The law does indeed give the government such powers but only in the rarest of rare cases and following due procedure and disclosure. There must be transparency in these decisions.

The Guild urges the government not to create a situation where the constitutionally and legally mandated freedoms of media representatives are compromised.

Shekhar Gupta	**AK Bhattacharya**	**Sheela Bhatt**
President	**General Secretary**	**Treasurer**

EGi
Editors Guild of India

June 09, 2019

The Editors Guild of India condemns the arrest of Noida-based journalist Prashant Kanojia and the editor and head of a NOIDA-based television channel, Nation Live - Ishita Singh and Anuj Shukla- by the Uttar Pradesh government. Mr Kanojia has been accused of uploading a post on Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on the social media and the Nation Live head and editor have been charged with having aired a video on the UP chief minister. The police action is high-handed, arbitrary and amounts to an authoritarian misuse of laws. The Guild sees it as an effort to intimidate the press, and stifle freedom of expression.

The FIR is based on the journalist sharing on Twitter the video of a woman claiming a "relationship" with the chief minister of Uttar Pradesh. The television channel had broadcast a video on the same issue. Whatever the accuracy of the woman's claims, to register a case of criminal defamation against the journalists for sharing it on the social media and airing it on a television channel is a brazen misuse of law. To give the police powers to arrest, provisions of Section 66 of the IT Act have also been added.

As with a recent case in Karnataka that the Guild spoke about, the FIR in this case is also not filed by the person allegedly affected but suo motu by the police. This is a condemnable misuse of law and state power.

The EGI also reiterates its demand that the defamation law should be decriminalised. The misuse of law in this specific case, as in Karnataka earlier, goes way beyond criminal defamation as many IT Act and Indian Penal Code provisions have been invoked in what looks like a motivated and vindictive action.

Shekhar Gupta	**Ashok Bhattacharya**	**Sheela Bhatt**
President	**General Secretary**	**Treasurer**

स्रोत

- Committee to Protect Journalists (CPJ)
- Risk and Research Analysis Group (RRAG)
- Newslaundry
- Newspapers, periodicals, websites and portals
- Twitter
- Facebook
- Indian Federation of Working Journalists (IFWJ)

About CAAJ

Committee Against Assault on Journalists (CAAJ) is a collective of independent media and civil society groups to defend press freedom and uphold the right to report without fear of intimidation. CAAJ is not a traditional journalist welfare body as such, neither a trade union nor a non-government organisation. Rather it is a process that is evolving since last couple of years to intervene on the issue of assault on journalists through various ways like documentation, research, seminars, lectures and active alliances.

CAAJ was introduced to the journalist fraternity first through a two-day national level convention against assault on journalists in New Delhi that saw journalists from more than ten states and families of some deceased journalists too. At this very first convention, CAAJ released a booklet documenting assaults in Indian journalists during last ten years.

In the last three years, CAAJ has organised three major meetings, one in Raipur, other in Chandigarh on the need of Journalist Protection Act and the last one in Varanasi where celebrated journalist P. Sainath delivered lecture on dangers of reporting to rural journalists.

CAAJ has continuously tracked cases of attacks on free voices and updated on its blog and social media handles. During last one and a half years, CAAJ has recommended assistance to assaulted scribes and networked with agencies that provide legal help to journalists in crisis. CAAJ has also advised CPJ, Asia on various occasions regarding media freedom in India.

After the completion of one year of its national convention, CAAJ called upon various stakeholders for stocktaking of the situation and future course of action in September 2019. Representatives from Delhi NCR, UP, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Jharkhand and Bihar attended the meeting. Representatives of IFWJ, Press Council, PIB Association, Kashi Patrakar Sangh, many members from Press Club of India, senior writers, journalists and members of civil society participated.

This meeting resulted in the expansion of alliances and process. Some interim sub-committees were formed like Screening Committee, Statement Committee, Legal Team and Social Media Committee. State co-ordinators were put in place.

The Apex sub-committee is the Statement Committee that includes senior and respected journalist Anand Swaroop Verma, Paranjoy Guha Thakurta, Shesh Narain Singh (Late), A K Lari, Rajesh Verma and Santosh Gupta.

Apart from Assault database from 2010-2018, CAAJ has published two major reports:

a) Attack on Journalists Covering Anti-CAA Protests

b) Republic in Peril

During two years of pandemic, CAAJ has been involved in documenting day-to-day cases of assault and harassment. Since the load of cases are much to verify and finalise hence the annual assault report of 2020 and 2021 has yet not been published.

Meanwhile, in the run-up to UP Assembly Elections 2022 CAAJ in association with UP PUCL has brought out this report covering last five years of press freedom status in Uttar Pradesh.

CAAJ plans to bring out its bi-annual assault report very soon.

Committee Against Assault on Journalists (CAAJ)

www.caajindia.org
committeeagainstassault@gmail.com
https://www.facebook.com/caajindia
https://twitter.com/caajindia